04 - अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

05 - 10 दिनों का उत्सव इस बार 13 दिन तक क्यों?

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 04 सितंबर, 2025

06 - हौसलों की उड़ान - एजुकेट गर्ल्स बनी 2025 रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड...

07 - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 325, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

शी ने मोदी को साधा, लेकिन उपमहाद्वीप पर पकड़ भी बढ़ाई

ऋषि गुप्ता

तियानजिन में शंघाई सुरक्षा सहयोग सम्मेलन (SCO) केवल एक वार्षिक क्षेत्रीय बैठक भर नहीं है। बीजिंग दरअसल वैश्विक व्यवस्था में छूटे हर हिस्से को भुनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ के नेताओं की मेज़बानी की–यह एक यूरेशियाई संगठन है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसमें चीन, रूस और भारत जैसे सदस्य शामिल हैं, जिससे यह एक अहम क्षेत्रीय मंच बन गया है।

शी ने लगभग सभी आए हुए नेताओं से, जिनमें पर्यवेक्षक सदस्य भी शामिल थे, द्विपक्षीय वार्ताएं कीं, लेकिन सबसे अहम रहा शी-मोदी का मिलना, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी पिछली बातचीत को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पिछले सात सालों में चीन की पहली यात्रा थी और पिछले साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य टकराव रोकने और शांति बनाए रखने के समझौते के बाद से यह सबसे अहम मुलाकात रही। एससीओ के दौरान हुआ यह भारत-चीन शिखर सम्मेलन, कूटनीतिक रिश्तों की बहाली के बाद बेहद ज़रूरी माना गया।

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और बाकियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक मीडिया का मानना है कि बड़ी ताकतें अब एक-दूसरे से तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगी। यह बात कुछ हद तक सही भी रही, क्योंकि चीन और भारत–एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने दोहराया कि वे 'प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि विकास के साझेदार हैं और उनके मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए।' भारत और चीन के बीच कारोबारी व व्यापारिक निर्भरता और टकराव की भारी कीमत को देखते हुए, दोनों का आपसी तालमेल साधना और पड़ोसी रिश्तों पर फिर से बातचीत करना एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

लेकिन भारत-चीन रिश्तों से ज़्यादा उम्मीद करना नई दिल्ली के लिए फिलहाल सिर्फ सतर्क आशा ही हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच भारत, चीन से नज़दीकी बढ़ाने की सोच सकता है। मगर सच यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर और रणनीतिक हित काफी अलग-अलग हैं।

क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन और मोदी-शी मुलाकात के अलावा, बीजिंग एक तीसरे बड़े आयोजन में भी व्यस्त रहेगा–विक्ट्री डे। यह चीन की जापान पर जीत और द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवादी ताकतों पर सहयोगी सेनाओं की जीत की 80वीं वर्षगांठ है। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेताओं की मौजूदगी यह दिखाएगी कि गैर-पश्चिमी दुनिया में चीन की लोकप्रियता बढ़ रही है, जहां इस परेड का ऐतिहासिक महत्व जापान को उसके औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाना रहा है, वहीं इस बार बीजिंग इस मौके का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए कर रहा है।

इसमें शक नहीं कि चीन ने अपनी सैन्य ताकत साबित कर दी है। भले ही अमेरिका के बराबर न हो, लेकिन यह कई पड़ोसी देशों, खासकर भारत, के लिए एक चेतावनी है, जो एलएसी पर लगातार सतर्क रहता है।

द्विपक्षीय समीकरणों और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से आगे बढ़कर, चीन अब विचारधारा का तालमेल बनाने और खुद को भारत के पड़ोस में केंद्रीय भूमिका में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के तमाम नेताओं में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ - ये सभी भारत के पड़ोसी देशों के नेता, जिन्हें बीजिंग रणनीतिक साझेदारी के ज़रिए अपने करीब ला रहा है–विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों देशों के जापान के साथ भी गहरे विकासात्मक रिश्ते और लोगों से लोगों का जुड़ाव रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस कार्यक्रम में शामिल होना उनकी सही कूटनीतिक नीति है। पाकिस्तान और मालदीव के मीडिया ने तो अपने नेताओं के चीन में जापान विरोधी कार्यक्रम में जाने पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाए, लेकिन नेपाल में ओली की भागीदारी को लेकर हैरानी जताई जा रही है। क्या ऐसी भागीदारी नेपाल की संविधान में बताई गई गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के अनुरूप है?

भारत इस बात से चिंतित है कि उपक्षेत्रीय परिदृश्य में चीन की पकड़ लगातार मज़बूत हो रही है। पिछले महीनों में चीन ने दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं को छोटे समूहों में बुलाया है, जून में कुनमिंग में पहली बार चीन-बांग्लादेश-पाकिस्तान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया और कुछ हफ्तों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक और त्रिपक्षीय बैठक की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के लंबे समय से निष्क्रिय रहने के बीच, चीन की ऐसी पहल हाल के वर्षों की सबसे अहम राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जा रही है।

बीजिंग के छोटे समूहों (मिनिलैटरल) में भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को शामिल करने की खासियत संभावित सहयोग से ज़्यादा उन चुनौतियों में है जो ये देश अपने साथ लाते हैं- अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवादित सीमा है और 1971 की आज़ादी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान का प्रतिद्वंद्वी बना दिया। इसके बावजूद चीन न केवल इन्हें एक मंच पर लाने में कामयाब रहा है, बल्कि खुद को अनिवार्य मध्यस्थ के रूप में पेश करने में भी सफल हुआ है। यह उपमहाद्वीप को लेकर बीजिंग की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह खुद को केंद्र में स्थापित कर रहा है, और इसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में आए बदलाव उसकी मदद कर रहे हैं। साथ ही, चीन भारत के पड़ोसियों को ढांचागत परियोजनाएं, व्यापारिक पहुंच और कूटनीतिक सहयोग दे रहा है, ताकि वे उसके 'राष्ट्रीय एकीकरण' के नैरेटिव को मान्यता दें, खासकर ताइवान पर। पहले जहां सिर्फ 'वन चाइना' सिद्धांत का ज़िक्र होता था, अब इसे और साफ शब्दों में लिखा जा रहा है।

यानी बीजिंग सिर्फ प्रभाव नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहा है जो या तो भारत-विरोधी रुख रखता है या फिर भारत के हित दांव पर होने पर इन देशों को रणनीतिक चुप्पी अपनाने पर मजबूर कर देता है। यह बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों और नेतृत्व की ओर इशारा करता है। मौजूदा हालात में, चीनी प्रभाव को समझना और उसे चुनौती देने के उपाय बनाना भारत के लिए ज़रूरी है।

आखिर में, बीजिंग की दोहरी रणनीति उसे संतुलन साधने में मदद करती है - जब व्यापार और कारोबार का फायदा हो तो भारत के प्रति मधुर बातें करना और साथ ही ट्रंप-नेतृत्व वाले वैश्विक ढांचे का कड़ा विरोध करना। इसी के साथ वह भारत के पड़ोस में चुपचाप अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पंजाब में हाहाकार, 23 जिलों के 1200 गांव डूबे

● बाढ़-बारिश ने ढाया कहर ● दिल्ली में उफान पर यमुना,लोगों के घरों में घुसा पानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में बुधवार को भी तेज बारिश जारी है। 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल-कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकूला के कई हिस्सों में 3-5 फीट तक पानी भरा है। यहां के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। अंबाला के सैकड़ों घरों में 2-4 फीट पानी भरा हुआ है। हथिनीकुंड बैराज से 67 207 मीटर पर बह रही है। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद किया गया है। यमुना बाजार-तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में पानी भरा है। यहां से 10 हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली में बुधवार को सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश जारी है। शहर के कई पॉश इलाके डूब गए हैं और सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में पानी भर गया है।

घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान (205 मीटर) के ऊपर

● हिमाचल में 1300 सड़कें बंद, यूपी के 20 शहरों में झमाझम- उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना के जलस्तर के बढ़ने से 1000 फार्महाउस में पानी भर गया। यहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। मथुरा में बाढ़ से करीब 900 परिवार प्रभावित हैं। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 श्मशान घाट पानी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मकान गिरने और लैंडस्लाइड में मौत हुई। आज सुबह कुल्लू में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई। कल शाम मंडी के सुंदरनगर में दो घरों पर लैंडस्लाइड हुई थी। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। आज मलबे से 4 शव निकाले गए हैं। राज्य के 7 जिलों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 970.28 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 104 फीसदी है, जबकि अब तक 800.1 एमएम बारिश होनी थी। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 939.8 एमएम है।

बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के प्यार का है हक

● सुप्रीम कोर्ट ने कहा-चाहे वह अलग देशों में ही रहते हों

एससी ने पिता को वीडियो कॉल करने की दे दी इजाजत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता-पिता के प्यार का हक है। भले ही दोनों अलग-अलग रहते हों या अलग-अलग देशों में ही क्यों ना हों। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला एक पिता को अपने बेटे से बात करने से रोकने के मामले में सुनाया। दरअसल, पिता भारत में रहता है और बेटा आयरलैंड में उनकी पत्नी के साथ है।

पैरेंट्स का झगड़ा, बच्चे के लिए ठीक नहीं

बच्चे को पिता या मां से दूर करना उसके विकास और भविष्य पर बुरा असर डालता है। माता-पिता का झगड़ा बच्चे को अनावश्यक संघर्ष में झोंक देता है, जो उसकी जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चे को पिता से दूर करना उसके प्यार और मार्गदर्शन से वंचित करना है। अदालत ने कहा कि बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वे मां और पिता दोनों के संपर्क में बने रहें, ताकि उनका संतुलित विकास हो सके। इस पूरे मामले को जानिए यह याचिका मनोज धनखर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 4 अक्टूबर, 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की थी। मनोज धनखर ने 26 नवंबर, 2012 को निहारिका से विवाह किया था। उनका बेटा 18 जनवरी, 2016 को पैदा हुआ। लेकिन 5 साल बाद अलग हो गए। तलाक के लिए आवेदन किया। इसके बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ।

सुप्रभात

जीना हो जाए जो आसान बुरा लगता है
देर से आए तो मेहमान बुरा लगता है
जिससे अच्छा मुझे लगता ही नहीं था कोई
मुफलिसी में वो ही इंसान बुरा लगता है
तुझको अहसान जताने की बुरी आदत है
इस लिए भी तेरा अहसान बुरा लगता है
यार हर रोज़ नया जख़्म नहीं देना था
रोज़ के रोज़ तो नुकसान बुरा लगता है
तू ने दिल को खुला दरबार बना रखा है
इस लिए भी तुझे दरबान बुरा लगता है
पहले पहले जो मेरे दिल में रहा करता था
अब उसे ही दिले नादान बुरा लगता है
तू दरिंदो से तो महफूज़ है तेरे घर में
क्या तुझे अब भी ये ज़िंदान बुरा लगता है
उन्होने आईना देखा नहीं होगा अनवर
वो जिन्हें चाक गिरेबान बुरा लगता है।

- जोन एलिया

चक्रवात से भारी बारिश, श्योपुर में मार्केट डूबा

हरदा में गांवों का संपर्क कटा, भोपाल में तेज बारिश; 5 बांधों के गेट खुले

भोपाल (नप्र)। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) की वजह से मध्यप्रदेश में बुधवार को भी अति भारी या भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इंदौर-उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी और 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर करीब दो बजे मौसम ने करवट ली और तेज बारिश हुई। शाम ढलते ही तेज बारिश का दौर था। जबलपुर में दोपहर करीब 12 बजे बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। डैम में कुल 21 गेट हैं। इनमें से 9 खोले गए हैं, शेष 12 से भी पानी लीक हो रहा है। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के तीन गेट, शिवपुरी में अटल सागर बांध मडीखेड़ा के दो, ग्वालियर में तिघरा डैम के 7 जबकि तवा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है।

जिलों में उर्वरक वितरण में अव्यवस्था के लिए कलेक्टर होंगे उत्तरदायी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य शासन हर स्थिति में किसानों के साथ

● उर्वरक वितरण व्यवस्था की हो सघन मॉनीटरिंग और अनुचित गतिविधियों पर करें कठोर कार्यवाही ● अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत के लिए हो तत्काल कार्यवाही ● जनहानि और पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलब्ध कराई जाए ● सीएम ने राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा की

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए। उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिले के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

सीएम बोले- कलेक्टर जिला नहीं चला पा रहे, हटाना होगा

सीएम ने जिलों में खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। रीवा में मंगलवार रात को खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन कलेक्टरों की प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, जो खाद वितरण के मामले में किसानों का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खाद की कमी के नाम पर सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे जिलों के कलेक्टरों को हटाने पर भी विचार किया जा सकता है।

● **किसानों को जिले में उपलब्ध उर्वरक की वास्तविक स्थिति से निरंतर करवायें अवगत-** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए। साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें, इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि, सहकारी बैंक, विपणन संघ के अधिकारी निरंतर सम्पर्क में रहें।

● **उर्वरक से संबंधित अवैध गतिविधियों के लिए हुई 53 एफआईआर और 88 लायसेंस किए निरस्त-** बैठक में खरीफ 2025 के लिए यूरिया, डी.ए.पी, एन.पी.के, एस.एस.पी, एम.ओ.पी तथा डी.ए.पी + एन.पी.के. की उपलब्धता, ट्रांजिट की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही नैनो एवं जैविक उर्वरक वितरण कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बताया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और नकली उर्वरक आदि से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 53 एफ.आई.आर. दर्ज की गई और 88 लायसेंस निरस्ती, 102 लायसेंस निलंबन सहित 406 विक्रय प्रतिबंधित की कार्यवाही की गई।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 04 सितंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ट्रंप कुढ़ते रहे, पर जर्मनी ने मानी भारत की ताकत

● ट्रेड डील पर विदेश मंत्री ने नई दिल्ली से कर दी बड़ी घोषणा ● कहा-यूरोप में शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकता है भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। ट्रेड वॉर के बीच रूस के करीबी दोस्त भारत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही खफा हों और कुढ़ रहे हों, लेकिन जर्मनी इस बात को मान रहा है कि भारत यूरोप में शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकता है। जर्मनी ने बुधवार को इस बात की तस्दीक भी कर दी।

जर्मनी ने भारत से कहा कि वह रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल यूरोप में शांति बहाली के लिए करे। दो दिन की भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जोहान वाडेफुल ने वैश्विक

चुनौतियों पर भी गहरी चर्चा की और भारत-जर्मनी के बीच व्यापार को दोगुना करने का भरोसा जताया।

वाडेफुल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता आने वाले महीनों में हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी का नाम लिए बिना कहा कि अगर दूसरे देश व्यापार में बाधाएं डालते हैं, तो हमें उन्हें कम करके जवाब देना चाहिए। बता दें कि पिछले साल दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीब 50 बिलियन यूरो का था। वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी इस व्यापार को दोगुना करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, और जयशंकर ने भी इस लक्ष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

● **यूरोप में शांति बहाली में भूमिका निभाए भारत**– यूक्रेन में शांति बहाली के मुद्दे पर जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन में शीघ्र शांति समझौते की आवश्यकता पर भी जोर दिया था, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम यूरोपीय लोग अपने अमेरिकी और यूक्रेनी मित्रों के साथ मिलकर इस युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि हम हमेशा अपने भारतीय मित्रों के साथ पूरी तरह सहमत नहीं होते, और इसीलिए मैंने आज इस बात के पक्ष में बात की कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल यूरोप में शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर देने के लिए करे और मैं आज यहां हुई खुली चर्चा के लिए आभारी हूं। शांति सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि का आधार है। सुरक्षा भविष्य के लिए एक चुनौती है और रहेगी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलीं पूर्व सीएम वसुंधरा

राजनीतिक गलियारों में मची हलचल, कयासों का दौर शुरू

जयपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत जोधपुर प्रवास पर हैं। वे 9 दिन तक जोधपुर रहेंगे। इस दौरान आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संघ प्रमुख से मुलाकात

की। राजे और भागवत के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। चूंकि राजे पिछले डेढ वर्ष से राजनैतिक रूप से हाशिए पर हैं। संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात के बाद राजनैतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजे स्वयं आरएसएस से जुड़ी रही हैं। संघ के तमाम वरिष्ठ नेताओं से उनके निकट के संबंध हैं। लिहाजा राजे और भागवत की मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजे को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।

भारत को और एस-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस

● रशियन अफसर बोले- हम आपस में बढ़ा रहे हैं सहयोग

एससीओ में मोदी बोले थे-भारत-रूस बुरे दौर में भी साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस और भारत के बीच एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। रूस की न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर के हवाले से बताया कि रूस भारत को एस-400 की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 एस-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। यह डील 5.4 बिलियन डॉलर (करीब ?48 हजार करोड़) थी। अब तक भारत को तीन स-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी दो की डिलीवरी

2026-27 तक हो जाने की उम्मीद है। ये वही डिफेंस सिस्टम है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। मोदी ने पुतिन को 'दोस्त' बताया था। इस सौदे को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिका ने भारत को एस-400 खरीदने पर सैंक्शन की चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ, इस डील पर चीन की भी नजर है, क्योंकि वो खुद इस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। फिलहाल, भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये सिस्टम मिल सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ी है।

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र सप्रे संग्रहालय की विशेष अध्ययन कक्षा में पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 88 छात्र बुधवार को माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान की विशेष अध्ययन कक्षा में सम्मिलित हुए।

मध्यप्रदेश के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

शिक्षक दिवस पर उल्लेखनीय कार्य के लिये नई दिल्ली में होंगे सम्मानित

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में पदस्थ हैं। आगर-मालवा जिले के श्री भेरूलाल ओसारा माध्यमिक शिक्षक शासकीय ईपीईएस माध्यमिक शाला खेरिया सुसनेर में पदस्थ हैं। प्रदेश के समस्त 55 जिलों में से 45 जिलों में 145 शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिये अपना पंजीयन कराया गया था। इसके बाद राज्य स्तरीय चयन समिति ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी थी। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयनित शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिये सम्मानित होने वाले शिक्षक प्रदेश के अन्य शिक्षकों के लिये भी प्रेरणा का कार्य करेंगे।

शीला पटेल प्राथमिक शिक्षक- श्रीमती शीला पटेल ने अपनी शाला में बच्चों को खेल-खेल में आनंदमयी शिक्षा दी है। उन्होंने गीत, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी मिशन (एफएलएन) का क्रियान्वयन किया है। इसी के साथ उन्होंने अवकाश के दिनों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये विशेष कक्षाओं का संचालन किया। श्रीमती शीला पटेल ने अवकाश के दिनों में समर कैम्प एवं विंटर कैम्प का आयोजन किया।

निलंबन के एक दिन बाद के. कविता ने छोड़ी बीआरएस

हैदराबाद (एजेंसी)। भारत राष्ट्र समिति द्वारा निलंबित किए जाने के एक दिन बाद पार्टी के संस्थापक व प्रमुख के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को हैदराबाद में एक पत्रकार वार्ता में के कविता ने अपने पिता और भाई के साथ संबंधों से जुड़े सवाल पर कहा कि विरोधी चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखर जाए। कविता ने अपने निलंबन को पूरी बीआरएस को नियंत्रित करने की साजिश का हिस्सा बताया। कविता ने अपने पिता केसीआर से नजर रखने के लिए कहा है।

अमेरिका की नाक के नीचे तैनात होगा फाइटर जेट!

चीन और वेनेजुएला में हो गई बातचीत, बढ़ेगा तनाव

काराकस (एजेंसी)। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बीते महीने ट्रंप प्रशासन के वेनेजुएला के पास पनडुब्बी और जंगी जहाज तैनात करने से तनाव शुरू हुआ। मंगलवार को हालात युद्ध जैसे हो गए, जब अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले जहाज पर हमला किया। इस

हमले में 11 लोग मारे गए। वेनेजुएला के प्रेसीडेंट निकोलस मादुरो ने अमेरिका की आक्रामकता का जवाब देने की बात कही है। साथ ही चीन से जे-10ए लड़ाकू विमानों की खरीद पर बात शुरू की है। चीन के जेट दुनिया का आधुनिक लड़ाकू विमानों में शुमार है। जे-10ए से ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट का सामना किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आध्यात्मिक गुरु श्री जग्गी वासुदेव को दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक एवं आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवाधिदेव महादेव से जग्गी वासुदेव के उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'पद्म विभूषण' से सम्मानित श्री जग्गी वासुदेव का दिव्य मार्गदर्शन समाज को आध्यात्मिक जागृति, सेवा और समरसता की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीं डोल ग्यारस पर्व की शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को मोक्षदायिनी जलझूलनी एकादशी (डोल ग्यारस) पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रदेश के कल्याण एवं लोकमंगल के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रीहरि सभी पर अनवरत सुख-समृद्धि की वर्षा करते रहें और जीवन में आरोग्यता प्रदान करें, यही मंगलकामना है।

राज्यपाल से केन्द्रीय सचिवालयीन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की भेंट

अपने अनुभव और प्रयासों से वंचित और गरीबों की मदद करें : राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारी अपने अनुभव को जनकल्याण के कार्यों में लगाए। हमेशा प्रयास करें कि आमजन की समस्याएं दूर हो। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले। ग़रीब, वंचित और जरूरतमंदों की मदद ही सच्ची जनसेवा है। यह पुण्य का काम है।

राज्यपाल श्री पटेल सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित 89वें ई-मिड-कॅरियर प्रशिक्षण के तहत केंद्रीय सचिवालयीन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, वरिष्ठ अवर सचिवों को संबोधित कर रहे थे। राजभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' के मूल मंत्र से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग तक पहुँच रही है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा जैसे विशेष कार्यक्रमों से जनजाति कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व कार्यों हो रहे हैं।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनकल्याणकारी राज्य के लिए सचिवालयीन अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका विशिष्ट होती है। सरकारी नौकरी व्यवसाय मात्र नहीं है, वंचितों के जीवन में खुशहाली लाकर समाज और देश का सुखद भविष्य बनाने की प्रतिबद्ध सेवा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आप जब भी दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में जाए तो ग़रीब, वंचित और ज़रूरतमंदों की समस्याओं को देखे, समझे और आत्मीयता से सुने। सरकारी धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें और इसके ख़र्च में मितव्ययिता का भी विशेष ध्यान रखें।

तीन पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत

2024 तक आए अल्पसंख्यक अब भारत में रह सकेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यकों पर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इन देशों से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को बिना पासपोर्ट रहने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि इन समुदायों के लोग अगर वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भी आए थे और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है, तब भी उन्हें रहने की छूट मिलेगी। पिछले साल लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस नए आदेश से 2014 के बाद आए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर पाक से आने वाले हिंदू परिवारों को।

पटना में पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो

● खामियों को जांचने के लिए ट्रायल रन हुआ, मंत्री भी देखने पहुंचे

बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी कर सकते हैं इसका उद्घाटन

पटना (एजेंसी)। बिहार की पहली मेट्रो का बुधवार को ट्रायल हुआ। मेट्रो का डीपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर इसका रन किया गया, ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों की पूरी जांच की जा सके। इसके बाद भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल होगा। ट्रायल एक हफ्ते तक चलेगा। ट्रायल रन के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच की। ताकि अगर ट्रायल के दौरान कोई तकनीकी परेशानी आती है तो उसे दूर किया जाएगा। मंत्री जीवेश मिश्रा ट्रायल रन देखने पहुंचे थे। पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पहले चरण में पटना मेट्रो को रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। पटना मेट्रो की रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी से जोड़ेगी। पहले योजना थी कि 15 अगस्त 2025 को ही पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया जाए, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से बढ़ा दी गई। अब संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री 15 को उद्घाटन करेंगे।

किम जोंग की बेटी पहली बार नॉर्थ-कोरिया के बाहर दिखीं

पिता के साथ चीन के विक्ट्री परेड में शामिल हुईं; दावा-अगली लीडर होंगी

बीजिंग (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ चीन की विक्ट्री परेड में उनकी बेटी किम जू ऐ भी पहुंची। यह पहला मौका था जब किम जू को देश के बाहर देखा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जू ऐ को किम जोंग का उत्तराधिकारी माना जाता है। जू 12 साल की हैं। वह 2022 से अपने पिता के साथ सैन्य परेड, हथियार परीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग के तीन बच्चे हैं, जिनमें किम जू के अलावा एक बेटा है। उनकी एक और संतान है, जो लड़का है या लड़की, यह स्पष्ट नहीं है। किम जू ऐ की इस यात्रा ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या किम अपनी बेटी को भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जू को को चीन ले जाना

उनकी बढ़ती हैसियत का संकेत है। बीजिंग रेलवे स्टेशन पर उन्हें अपने पिता के साथ खड़ा देखकर यह साफ हो गया कि विदेश में भी उन्हें उत्तर कोरिया का नंबर 2 माना जा रहा है।

कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली

कोर्ट ने कहा, जांच में सहयोग नहीं किया तो निरस्त हो जाएगी

इंदौर। विवादास्पद कार्टून बनाने वाले हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने मालवीय को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जांच में सहयोग नहीं करने पर जमानत रद्द की जा सकती है। मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विवादित कार्टून बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इससे पहले 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मालवीय ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। इसके बाद मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। एफआईआर के अनुसार, मालवीय के कार्टून में आरएसएस की वर्दी पहने एक व्यक्ति को शर्ट्स उतारे हुए और प्रधानमंत्री मोदी को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून से भावनाएं आहत होने पर इंदौर के विनय जोशी ने पुलिस से शिकायत कर दी थी। पोस्ट में कथित तौर पर भगवान शिव से जुड़ी टिप्पणियां भी थीं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपमानजनक पाया।

माफीनामा लिखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। मालवीय ने कोर्ट में कहा कि वह आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अशोभनीय व्यंग्य चित्र बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफीनामा प्रकाशित करेंगे। यह सुनवाई 19 अगस्त को हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन में माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

मालवीय ने माफी मांगी

25 अगस्त को मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, मुझे 1.05.2025 को प्रकाशित किए अपने फेसबुक पोस्ट पर गहरा खेद है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान पूर्वक कहता हूं, कि मेरा किसी भी कार्टून या पोस्ट से, किसी समुदाय, जाति, धर्म से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तनाव भड़काना या जानबूझकर किसी पार्टी या व्यक्ति का अपमान करने का कतई कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था। मेरा अपनी किसी भी फेसबुक पोस्ट से किसी सार्वजनिक व्यक्ति, संगठन या समुदाय के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। अनजाने में हुए इस कृत्य का मुझे बहुत खेद है 7 मैं पूरे हृदय और ईमानदारी से बारम्बार माफी मांगता हूं। मैं यह मानता हूं और सर्वदा ध्यान रखूंगा कि भाईचारा और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना मेरी भी ज़िम्मेदारी है और भविष्य में मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा।

कान्ह-सरस्वती नदी रिवर फ्रंट के लिए इंदौर ने 671 करोड़ रू मांगे

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने केंद्रीय मंत्री खट्टर से चर्चा की

इंदौर। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की जीवनदायिनी कान्ह (28 किमी) और सरस्वती (13 किमी) नदी के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 671.69 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृत करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। उन्होंने आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा के करनाल में आयोजित महापौर परिषद की बैठक के दौरान पृथक चर्चा की। महापौर ने बताया कि इस परियोजना में स्टोन पिचिंग, वॉक-वे, उद्यान, विद्युत सज्जा और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य सम्मिलित हैं। इसके पूर्ण होने पर शहर के मध्य एक आकर्षक व रमणीय रिवर फ्रंट तैयार होगा, जो न केवल नागरिकों बल्कि पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा।गौरतलब है कि हरियाणा पहली बार अखिल भारतीय महापौर परिषद की प्रतिष्ठित 53 वीं वार्षिक आम सभा की मेजबानी कर रहा है। इस दो दिवसीय बैठक में देशभर के महापौर शामिल हुए हैं, जहां शहरी विकास से जुड़े अहम विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। महापौर भार्गव ने कहा कि स्वच्छता और नवाचार में लगातार देश में अग्रणी इंदौर अब नदी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी मिसाल कायम करेगा।

डकैती की योजना में 4 गिरफ्तार

इंदौर। पुलिस ने अपराधियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तलवार,लोहे की रॉड, धारदार संतूर,लाल मिर्च पाउडर के पैकेट और एक ईको वैन बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी देवास और रतलाम जिले के कंजर डेरों से जुड़े हैं और इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी व एडीसीपी दिशेष अग्रवाल के निर्देशन में द्वारकापुरी पुलिस ने सूचना पर स्कीम नंबर 71 क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार बदमाशों में जितेंद्र सिंह (32) मंदसौर, जागरण उर्फ चीकू झाला (28) देवास,नवीन चौहान (20) और संजय जैसवाल (27) रतलाम निवासी शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चंदन नगर थाना क्षेत्र के नावदा पंथ स्थित एक फार्म हाउस में 24 अगस्त की रात डकैती करने की वारदात को स्वीकार किया।

फोटो स्टूडियो में आग से लाखों का माल जला

इंदौर। द्वारकापुरी इलाके में फोटो स्टूडियो में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। एक घंटे बाद दमकलें पहुंचने से नुकसान ज्यादा हुआ। इसके पहले आसपास के लोगों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया था। घटना सोमवार देर रात अंकल गली 60 फीट रोड स्थित एसआर स्टूडियो और पर्सनालिस्ट गिफ्ट सेंटर की है। हादसे में स्टूडियो का पूरा सेटअप, कैमरे और गिफ्ट आइटम जल गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन गाड़ियां काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचीं। लोगों का कहना था कि अगर दमकल दल समय पर पहुंच जाता तो नुकसान कम हो सकता था। इस दौरान द्वारकापुरी पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई सुशील पटेल अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बोरिंग से पानी डालकर आग को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस और रहवासियों ने मिलकर दुकान का शटर तोड़ा और अंदर रखे कुछ सामान को बाहर निकालने का प्रयास किया।

निर्मला सप्रे केस की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में नहीं, याचिका खारिज

जबलपुर में दोबारा याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र

इंदौर। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार में विचारणीय न होने के आधार पर यह फैसला सुनाया। सप्रे की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने अंतिम आदेश पारित किया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे मुख्य हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष दोबारा याचिका पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश सोमवार को जारी किया गया।नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रिट पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस से निर्वाचित विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। याचिका में मांग की गई थी कि सप्रे ने पार्टी बदली है तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इसके लिए पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पत्र भेजा था लेकिन उस पर 90 दिन की तय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

याचिका में कहा था कि संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार कोई विधायक दल बदलता है, उसकी विस से सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। हाईकोर्ट में हुई बहस के दौरान सिंगार की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने तर्क में कहा कि या तो कोर्ट इस पर निर्णय दे या विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित करे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने तर्क रखे।

अनवर का कश्मीर में बना आर्म्स लाइसेंस फर्जी निकला, केस दर्ज

लाइसेंस रामबन जिले में बना, इसे कठुआ से रिन्यू कराया

इंदौर। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ सदर बाजार पुलिस ने फर्जी आर्म्स लाइसेंस का एक और केस दर्ज किया है। पुलिस ने घर से मिले आर्म्स लाइसेंस को लेकर जांच की थी। जिसमें लाइसेंस फर्जी निकला है। इसके बाद अफसरों को जानकारी दी गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।

सदर बाजार पुलिस भी इस मामले में अनवर की गिरफ्तारी करेगी। पुलिस उपायुक्त कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि वर्ष 2024 में कादरी ने सदर बाजार में रहने वाले वर्ग विशेष के युवक से विवाद हुआ था। इसके कुछ दिन बाद कादरी ने युवक को जान से मारने की नीयत से बंदूक निकाली थी। तब उसके खिलाफ पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया था। बंदूक को लेकर पीड़ित युवक ने लायसेंस को लेकर आशंका जताई थी। युवक की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो चौकाने वाली

जानकारी सामने आई।

पता चला कि कादरी ने बंदूक का लायसें रामबन (जम्मू कश्मीर) का होना बताया। जब पुलिस ने रामबन जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी हासिल की तो पता चला कि वहां से कादरी का लाइसेंस नहीं बना। कुछ दिन बाद जब पुलिस ने कादरी से पूछा तो उसने लाइसेंस को कठुआ जिले से रिन्यू कराना बताया। लाइसेंस का यूआईडी नंबर भी गलत होना पाया गया। दोनों जिलों से लाइसेंस को लेकर इंकार करने पर कादरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया।

इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट 16 सितंबर से

स्टार एयर शुरू कर रही, इंदौर से दो नई हवाई सेवाएं

इंदौर। अब इंदौर से गोंदिया (महाराष्ट्र) के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंदौर से बेंगलुरु के लिए भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। दोनों ही फ्लाइट 16 सितंबर से शुरू होंगी। इन फ्लाइट का संचालन स्टार एयर द्वारा किया जाएगा। स्टार एयर इंदौर एयरपोर्ट से एक बार फिर अपना संचालन इस फ्लाइट के साथ शुरू करने जा रही है। इंदौर से गोंदिया की उड़ान के लिए उसने अनुमति ले ली है। स्टार एयर कंपनी 2 साल पहले इंदौर से किशनगढ़ और बेलागावी की उड़ानों का संचालन कर चुकी है। ट्रैवल एजेंट्स ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रेसिडेंट हेमेन्द्र सिंह जादौन ने बताया कि इंदौर से स्टार एयर बेंगलुरु और गोंदिया के लिए फ्लाइट फिर संचालन

शुरू करने जा रही है। यह इंदौर की एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। इंदौर से बेंगलुरु और महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को एक और कनेक्टिविटी का साधन मिलेगा। कंपनी ने इससे पहले मार्च अंत से लागू हुए समर शेड्यूल में भी इंदौर से गोंदिया और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव दिया था।

सप्ताह में तीन दिन संचालन- स्टार एयर कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी इंदौर से बेंगलुरु और इंदौर से गोंदिया के लिए सप्ताह में तीन फ्लाइट का संचालन करेगी। दोंनो ही फ्लाइट्स का संचालन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा।

इंदौर से बेंगलुरु

- फ्लाइट नंबर एस5 204 बैंगलुरु से 2.30 बजे उड़ान भरकर दोपहर 4.30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर आएगी।
- फ्लाइट नंबर एस5 205 इंदौर एयरपोर्ट से 7.50 बजे उड़ान भरकर रात 9.45 बजे बेंगलुरु जाएगी।

इंदौर से गोंदिया

- फ्लाइट नंबर एस5 460 इंदौर से 5 बजे उड़ान भरकर शाम लगभग 6 बजे गोंदिया पहुंचेगी।
- फ्लाइट नंबर एस5 459 गोंदिया से 6.25 बजे उड़ान भरकर रात 7.20 बजे इंदौर पहुंचेगी।

लैटिन अमेरिका से इंदौर की स्वच्छता देखने आया 4 देशों का प्रतिनिधिमंडल

इसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला के प्रतिनिधि

इंदौर। विश्व में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके इंदौर ने 8वीं बार खिताब जीतकर फिर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। लैटिन अमेरिका के चार देशों ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला का एक प्रतिनिधिमंडल इंदौर के अनूठे स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करने शहर पहुंचा। इस मंडल में शामिल अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इंदौर की कचरा प्रबंधन प्रणाली को करीब से समझने की इच्छा जताई।

मंगलवार को इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी कोठी में विदेशी प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

निगम आयुक्त ने मेहमानों को इंदौर की स्वच्छता यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण (सेग्रीगेशन), पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग), और कचरे से मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर के गोवर्धन बायो-सीएनजी प्लांट और ट्रेंचिंग ग्राउंड का दौरा किया, जहां शहर के कचरे से मीथेन गैस निकालकर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर की नवीन तकनीकों, सतत विकास के प्रयासों और कचरे से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया की जमकर सराहना की। लैटिन अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल न केवल भारत बल्कि समस्त विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल है। हम इस मॉडल को अपने देशों में लागू करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। यह दौरा इंदौर के स्वच्छता मॉडल की वैश्विक स्वीकार्यता को रेखांकित करता है और शहर की 'स्वच्छता राजधानी' के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है।

प्रिया ठाकुर बनकर की दोस्ती, ठग लिए 50 हजार

इंदौर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बदमाश लगातार गंभीर वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। कई बार युवतियां ऐसे बदमाशों की दोस्त बनाकर अपना शोषण करा लेती है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आरोपियों ने युवती के नाम से फर्जी आईडी बनाकर युवक को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बातचीत के बाद उसे बायपास पर मिलने बुलाया गया और फिर डराकर उसके अकाउंट से 50 हजार रुपए खुद के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

बदमाश हले भी इस तरह कई लड़कों को लूट चुके हैं। पुलिस ने बताया कि लवकुश कॉलोनी निवासी राहुल ने शिकायत में कहा कि उसकी इंस्टाग्राम पर प्रिया ठाकुर नाम की युवती से दोस्ती हुई थी। चैटिंग के दौरान युवती ने उसे बायपास के सुनसान इलाके में बुलाया। जब राहुल वहां पहुंचा तो तीनों आरोपी पहले से मौजूद थे। आरोपियों की पहचान पंकज पिता सुंदरलाल खातकर निवासी लसूडिया, यश सोलंकी निवासी निरंजनपुर और विजेंद्र गुप्ता के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फर्जी प्रोफाइल बनाकर उन्होंने राहुल को जाल में फंसाया था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने इसी तरह और लोगों को भी अपने झांसे में लेकर ठगी की है।

19 सितंबर तक 'मालवा एक्सप्रेस' शार्ट टर्मिनेट, अंबाला तक जाएगी

वैष्णो देवी नहीं जाएगी, कुछ और ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट, निरस्त

इंदौर। उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। लगातार निरस्त हो रही मालवा एक्सप्रेस को शार्ट टर्मिनेट किया गया है। अब यात्री महू से अंबाला तक यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन अंबाला से श्री माता वैष्णो देवी तक शार्ट टर्मिनेट की गई है। इसके कारण वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना होगा।

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 से 19 सितंबर तक डॉ अंबेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस अंबाला रेलवे स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होगी। अंबाला से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक निरस्त रहेगी। इसी तरह तीन से 20 सितंबर तक श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-डॉ अंबेडकर एक्सप्रेस अंबाला रेलवे स्टेशन से शार्ट ओरिजिनेट होगी और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से अंबाला तक निरस्त रहेगी।

यह ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट

2 से 19 सितंबर तक डॉ अम्बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12919 डॉ अम्बेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस, अंबाला रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अंबाला से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक निरस्त रहेगी। 3 से 20 सितंबर, 2025 तक श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12920 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-डॉ अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, अंबाला रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से अंबाला तक निरस्त रहेगी।

ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

- 8, 15, 22 एवं 29 सितंबर को इंदौर उधमपुर एक्सप्रेस निरस्त।
- 3, 10, 17 एवं 24 सितंबर को उधमपुर- इंदौर एक्सप्रेस निरस्त।
- 4 एवं 5 सितंबर को बांद्रा-टर्मिनस वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस निरस्त।
- 2, 3 एवं 5 सितंबर को वैष्णो देवी कटड़ा-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त।
- 4 सितंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-गांधीधाम एक्सप्रेस निरस्त।

10 पुलिस अधिकारियों को भावभीनी विदाई

इंदौर। इंदौर पुलिस की नौकरी में वर्षों तक ईमानदारी और कर्मठता से सेवा देने वाले 10 अधिकारी मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। सभी अधिकारियों का वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मान किया। सम्मान से अभिभूत होकर उन्होंने भावुक मन से खट्टी मीठी बातें बताई। पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) मनोज श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) प्रकाश परिहार, अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सीमा अलावा, सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) संजय सिंह बैस, रक्षित निरीक्षक दीपक पाटील ने सहायक पुलिस आयुक्त धैर्यसिंह येवले, निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक हनुमान सिंह, सहायक उप निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह, सहायक उपनिरीक्षक भरतलाल, सहायक उपनिरीक्षक कैलाश गावड़े, प्रधान आरक्षक प्रदीप कुमार, रविन्द्र सिंह कुशवाह, रामनरेश को विदाई दी। सेवानिवृत्त अधिकारियों का श्रीफल, मोमेंटो व पुष्प माला भेंट की गई। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा कि आप सभी ने चुनौतीपूर्ण ड्यूटी करते हुए जनता की सेवा की है, अब परिवार को समय देने की बारी है। उन्होंने कहा कि, अभी तक इन्होंने सर्विस कर आपका हर प्रकार से ध्यान रखा है, अब आप लोगो की बारी है। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सभी साथियों को आश्वासन दिया कि, ये पुलिस परिवार अब भी उनका परिवार है, वे जब चाहे यहां आकर अपनी समस्याएं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते है। अंत में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने साथियों से मिलकर भावुक मन से विदाई ली।

शादी का झांसा देकर युवती से दिल्ली के युवक ने दुष्कर्म किया, शिकायत दर्ज

शादी की बात करने इंदौर आया और वापस जाकर इंकार किया

इंदौर। पुलिस ने एक 32 साल की महिला की शिकायत पर दिल्ली में रहने वाले सिख व्यक्ति के खिलाफ रेप के मामले में केस दर्ज किया। आरोपी से पीड़िता की पहचान दिल्ली घूमने के दौरान एक मॉल में हुई थी। आरोपी ने खुद का बिजनेस बताया था। इसके बाद पहचान कर शादी का झांसा देकर रेप किया। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है खजराना पुलिस के मुताबिक 32 साल की पीड़िता सोमवार को थाने आई। शिकायत पर करण सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी हेमकुंड साउथ दिल्ली के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि जुलाई में वह भाई के जन्मदिन पर दिल्ली घूमने गई थी। यहां पर वसंत कुंज में डीएलएफ मॉल में एक शोरूम में चश्मे देख रही थी। तब एक सिख व्यक्ति पास आया और नाम पता पूछा। उसने बताया कि उनका माइंस का बिजनेस है। इसके बाद उन्होंने मोबाइल नंबर ले लिया। तीन दिन बाद पीड़िता फ्लाइट से इंदौर आई। इसके बाद करण सिंह से एक दो बार मोबाइल पर बात हुई, तो उसने कहा कि वह उसे पसंद करने लगा है। और उससे शादी करने का मन है। इसके बाद मां भाई से पीड़िता ने करण को लेकर बात की। उन्हें फोटो दिखाने पर उन्होंने हां कर दी। वह पीड़िता से वीडियो कॉल पर बात करने के लगा। उसके बिजनेस को लेकर माइंस के फोटो वीडियो शेयर करता रहा। 17 जुलाई को उसने इंदौर खजराना आकर मिलने की बात कही। जिसमें मां और भाई से मुलाकात करने के लिए कहा। करण सिंह इंदौर आने के बाद मां और भाई जब काम से गए तो वह घर पर ही रहा। इस दौरान उसने संबंध बनाए।

संबंध बनाकर इंकार

तब करण को रोका तो उसने कहा कि अब सब लोग राजी हैं। इसके बाद 15 दिन में शादी की बात की। जब करण सिंह ने 15 दिन बात नहीं की तो उसे कॉल किया तब वह कहने लगा कि वह करोड़पति घर की बहू बनने के सपने देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपशब्द कहे। इसके बाद कहा कि उसके कई लड़कियों से संबंध हैं। पीड़िता से करण सिंह ने कहा कि वह फॉर्म हाउस पर इस तरह की कई लड़कियों को लेकर आता है। उसने शादी की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद डिप्रेशन में रहने लगी सोमवार को माता-पिता और भाई ने जब पूछा तो उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद थाने जाकर करण सिंह के खिलाफ पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले में आरोपी की तलाश कर रही है।

संपादकीय

कुदरत का कहर- दोषी कौन ?

इस समय समूचे उत्तर-पश्चिमी भारत में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर बना हुआ है। मौसम परिवर्तन इसका बड़ा कारण है। उसका मिजाज भांपना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। उसके आगे मौसम भी भविष्यवाणियां करने वाले यंत्र भी बेबस साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल मई-जून के महीने में देश के कई इलाक़ों में भीषण हीट वेव देखी गई थी। अब पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाक़े भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पिछले दो महीनों में मौसम से जुड़ी घटनाओं में देश के अलग-अलग हिस्सों में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लापता हैं। इनमें मौसम में आए बदलाव की वजह से हुए सड़क हादसों में मारे गए लोग भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए भारी बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। मौसम में इस बदलाव को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक़, हीट वेव और मानसून के पैटर्न में हो रहे बदलाव का कारण पृथ्वी का गर्म होना है। भारत के मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ. केजे रमेश कहते हैं, इन एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन में सीधा संबंध है। ग्रीनपीस से जुड़े शोधकर्ता आकिज़ भट भी मानते हैं कि अभी मौसम की वजह से जो आपदाएं आ रही हैं, ये सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर है। आलम यह है कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ आने की आशंका ज़ाहिर की गई है और प्रशासन अलर्ट पर है। सबसे गंभीर हालात उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हैं। भूस्खलन की वजह से फ़सलों को नुक़सान हुआ है। सड़कें और पुल बह जाने से कई इलाक़ों में आवागमन ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर में अगस्त महीने में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है और कई इलाक़ों में लोग बेहाल हैं। पांच अगस्त को उत्तरकाशी के हर्षिल और धराली गांव में अचानक आए सैलाब से दो लोगों की मौत और 67 लोग (सरकारी आंकड़ों के मुताबिक) लापता हुए। कई घरों और होटलों के साथ सेना का कैंप भी बह गया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के अलग-अलग इलाक़ों में अब तक कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है और 12 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। 15 हज़ार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। क़रीब एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ के पानी में डूबी है। विशेषज्ञों के मुताबिक़ भीषण गर्मी पहले भी पड़ती थी और भारी बारिश भी होती थी लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी हैं। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर सहमत हैं और इसका सबसे बड़ा कारण वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा को माना जाता है। इसके अलावा पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास और निर्माण कार्य भी इसका प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेलगाम और विकास गतिविधियां और प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में मानवीय दखल इसका बड़ा कारण है। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। हालात सुधरने की संभावना नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारें इस बात को गंभीरता से समझे और उसके मुताबिक नीतियां बनाएं। प्रकृति राजनीति नहीं समझती। उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन प्रकृति को मंजूर नहीं है।

नजरिया

डॉ. विनोद सेन
सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ के कारण कई प्रमुख क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो सालाना लगभग 2.3 लाख करोड़ का योगदान देता है और भारत के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इस टैरिफ वृद्धि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पहले 25 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और निर्यातकों में भारी चिंता व्याप्त है। इसी तरह, रत्न और आभूषण क्षेत्र, जिसका लगभग एक-तिहाई निर्यात अमेरिका को होता है, अब प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रह गया है, जिससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के संकट का खतरा बढ़ गया है। समुद्री और कृषि उत्पाद जैसे झींगा, बासमती चावल और चाय भी 26 प्रतिशत के नए टैरिफ से प्रभावित हो रहे हैं, जो उनकी लाभ मार्जिन और निर्यात मात्रा को कम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ऑटो पार्ट्स, कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा और जूते, तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्र भी इस टैरिफ के दायरे में आने से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर अमेरिकी बाजार में मांग है।

भारत और अमेरिका लंबे समय से एक-दूसरे के प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहे हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया जो बुधवार 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया, जिससे भारत के अरबों डॉलर के व्यापार पर असर पड़ेगा। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक की उच्च दर से टैरिफ लगाने से दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच व्यापारिक तनाव की एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है। यह निर्णय भले ही भू-राजनीतिक और व्यापार नीति के पुनर्संतुलन से प्रेरित हो, लेकिन इसके प्रभाव भारत की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार संतुलन और समग्र आर्थिक दिशा पर गहरे और बहुआयामी हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने से भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। भारतीय निर्यात में स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएँ और कृषि उत्पादों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में टैरिफ बढ़ने से भारतीय वस्तुएँ अमेरिकी बाजार में महंगी हो जाएँगी, जिससे मांग घटने और निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात-आधारित रोजगार पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी गहरी चोट पहुँचेगी। जिसके कारण भारतीय निर्यात घट सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ के कारण कई प्रमुख क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। वस्त्र और परिधान क्षेत्र, जो सालाना लगभग 2.3 लाख करोड़ का योगदान देता है और भारत के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इस टैरिफ वृद्धि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पहले 25 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और निर्यातकों में भारी चिंता व्याप्त है। इसी तरह, रत्न और आभूषण क्षेत्र, जिसका लगभग एक-तिहाई निर्यात अमेरिका को होता है, अब प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रह गया है, जिससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के संकट का खतरा बढ़ गया है। समुद्री और कृषि उत्पाद जैसे झींगा, बासमती चावल और चाय भी 26 प्रतिशत के नए टैरिफ से प्रभावित हो रहे हैं, जो उनकी लाभ मार्जिन और निर्यात मात्रा को कम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ऑटो पार्ट्स, कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा और जूते, तथा फर्नीचर जैसे क्षेत्र भी इस टैरिफ के दायरे में आने से गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर अमेरिकी बाजार में मांग है। दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं क्योंकि इन्हें कुछ छूट मिली हुई है और इनकी अमेरिकी मांग स्थिर बनी हुई है, जो व्यापक व्यापारिक झटकों

से राहत का स्त्रोत हैं। व्यापक आर्थिक स्तर पर, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष लगभग 3.7 लाख करोड़ का अब घाटे में बदलने का जोखिम है, यदि सभी निर्यातों पर नए टैरिफ लागू होते हैं। भारत के घरेलू संकेतक जैसे विनिर्माण पीएमआई, ई-वे बिल और उपभोक्ता खर्च मजबूत बने हुए हैं, लेकिन बाह्य क्षेत्र में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। वित्त मंत्रालय ने इन प्रभावों को 'विलंबित लेकिन महत्वपूर्ण' बताया है और व्यापार नीति में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। टैरिफ की अनिश्चितता ने विशेष रूप से निर्यात-आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों के निवेशकों की भावना को प्रभावित किया है, जिससे भारतीय रुपये के अवमूल्यन का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार और जीएसटी तथा विनियमन में सुधार दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करते हैं जो इन प्रभावों को संतुलित करने में सहायक हैं। इस प्रकार, भारत के कई मुख्य उद्योग टैरिफ के प्रभाव से चोटिल हुए हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए नीति स्तर पर सतत सुधार और रणनीतिक कदम आवश्यक हैं।

इस परिस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अपने व्यापारिक साझेदारी के दायरे को और विस्तृत करना होगा ताकि किसी एक देश की नीतिगत अस्थिरता से उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर न पड़े। भारत ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ईएफटीए के साथ व्यापार समझौते के लिए वार्ताएँ कर रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में नुकसान की भरपाई की जा सके। इसी बीच सरकार 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और निर्यात को नया बल मिले। साथ ही, सरकार को छोटे और मध्यम उद्यमों को विशेष समर्थन और सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकें। निर्यातकों के लिए सस्ते वित्त और मार्केटिंग सहायता को बढ़ावा देना तथा घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स दरों में कमी करना भी एक प्रभावी कदम हो सकता है। फिर भी अल्पकालिक चुनौतियाँ बरकरार हैं क्योंकि अमेरिका का टैरिफ सीधा-सीधा भारतीय वस्तुओं की लागत को बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत अपने निर्यात की विविधता बढ़ाए, उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान दे और मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से लागू करे तो वह अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है,वहीं अमेरिका भी चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत को एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार के रूप में देखता है, इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश टैरिफ विवाद को किसी न किसी स्तर पर संतुलित करेंगे। कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है- यह भारत को अपनी नीतियों में आत्मनिर्भरता की ओर धकेलता है और उसे वैश्विक व्यापारिक साझेदारी में विविधता लाने की प्रेरणा देता है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज आवश्यकता है कि भारत दीर्घकालिक रणनीति के तहत अपनी निर्यात नीति को अधिक लचीला बनाए, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाए और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संवाद को मजबूत रखे, ताकि व्यापारिक विवाद राजनीतिक साझेदारी पर हावी न हो सके और भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की राह पर बनी रहे।

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने भारतीय व्यापार को एक बड़ा झटका दिया है, लेकिन इसे एक चुनौती के साथ-साथ अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अब समय है कि भारत अपनी व्यापार नीतियों में बदलाव लाए और अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए अफ्रीका, यूरोप, चीन तथा अन्य उभरते बाजारों के साथ नए व्यापारिक संबंध स्थापित करे। व्यापार के इन विविधीकरण से न केवल निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मजबूती आएगी। साथ ही, भारतीय उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीक और नवाचार में व्यापक निवेश करना आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता और अनोखे डिजाइन वाले उत्पादों का उत्पादन कम लागत में करना होगा ताकि वे अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित होने के बावजूद ग्लोबल बाजार में आकर्षक विकल्प बन सकें। टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, और समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्रों में तकनीकी अपग्रेड और गुणवत्ता मानकों को बढ़ा कर भारतीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत को घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना होगा ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगा बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ाएगा। व्यापार में इस पुनर्संरचना से देश को दीर्घकालिक लाभ होगा और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ज्यादा लचीला बनायेगा।

इस प्रकार, अमेरिका के टैरिफ नीति द्वारा उत्पन्न संकट से सीख लेकर, भारत अपनी व्यापार रणनीति को निखारकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह और मजबूत कर सकता है। यह समय है कारोबार को व्यापक दृष्टिकोण से देखने और नवाचार के बल पर भविष्य के नए अवसर तैयार करने का।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

खामोश की जातीं, पर्यावरण संरक्षण की आवाजें

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर मंडरा रहे भयावह संकट को उजागर करने वाली हाल की 'ग्लोबल विटनेस' रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2012 से अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए 2,106 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इनमें से एक-तिहाई से अधिक हत्याएँ लैटिन अमेरिका में हुईं। अकेले वर्ष 2023 में कम-से-कम 196 लोगों की जानें गईं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग आज भयंकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खतरों का सामना कर रहे हैं। खनन, औद्योगिक और निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ खड़े होने के कारण ये कार्यकर्ता सत्ता और पूंजी के निशाने पर आ जाते हैं।

'ग्लोबल विटनेस,' जो बीते ढाई दशक से तेल, गैस, खनन और वन क्षेत्रों में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय शोषण की जाँच करता रहा है, ने इस रिपोर्ट को 200 से अधिक देशों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 90 फीसदी से अधिक लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है और 25 फीसदी से अधिक पर हिंसक हमले हुए हैं। 70 फीसदी हत्याएँ खनन, बड़े बांधों और जंगलों की कटाई के खिलाफ आंदोलन करने वालों की हुई हैं।

रिपोर्ट बताती है कि विकास की आड़ में स्थानीय समुदाय, विशेषकर आदिवासी, किसान, महिलाएं और मछुआरे, खास निशाने पर हैं। जब ये समुदाय अपनी ज़मीन, जंगल और नदियों के संरक्षण की आवाज उठाते हैं, तो या तो उन्हें झूठे मामलों में फँसाया जाता है या फिर वे गोलियों का शिकार होते हैं। कोलंबिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, कांगो और होंडुरास जैसे देश इस हिंसा के गवाह हैं। यहां हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वे अपने जंगल, नदियों, खेतों और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं।

कोलंबिया लगातार दूसरे साल सबसे खतरनाक देश माना गया था जहाँ 2023 में 79 पर्यावरण रक्षकों की हत्याएं हुईं। यह लगातार चौथा वर्ष है, जब कोलंबिया में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज हुई हैं। वर्ष 2012 से अब तक ऐसी 461 हत्याएं हुई हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले अधिक हैं। इसके बाद ब्राजील में 34, मैक्सिको और होंडुरास में 18-18 और फिलीपींस में 11 पर्यावरण रक्षकों की हत्याएं हुईं। मध्य अमेरिका पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र बन चुका है, जहां प्रति व्यक्ति हत्याओं की दर सबसे अधिक रही है।

इनमें से अधिकांश हमले वनों की रक्षा करने वालों, खनन विरोधी आंदोलनों में शामिल लोगों और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों पर हुए हैं। अक्सर ये हमले संगठित अपराधियों, सरकार समर्थित ठेकेदारों या निजी कंपनियों के इशारों पर होते हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड में कार्यकर्ताओं को 'रेड टैगिंग' (देशद्रोही) करार देकर मारा या गायब किया जा रहा है। इन मामलों में भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 के बीच भारत में 71 पर्यावरण रक्षकों की हत्या दर्ज की गई। इनमें से कई पत्रकार थे, जो ज़मीन अधिग्रहण और अवैध खनन जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वर्ष 2014 के बाद मारे गए 28 पत्रकारों में से 13 पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे थे। भारत में रेत-माफिया और अवैध खनन पर लिखने वाले पत्रकारों को खासकर निशाना बनाया गया।

रिपोर्ट इंगित करती है कि भारत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों और पत्रकारों पर बढ़ती निगरानी, गिरफ्तारी और बदनाम करने की घटनाओं में तेज़ी आई है। साथ ही, उनके खिलाफ 'गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम' (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सरकारों द्वारा कार्यकर्ताओं को वर्षों जेल में रखना, उनकी जमानत रोकना और उन्हें 'राष्ट्रविरोधी' करार देना जैसी घटनाएं कई राज्यों में सामने आई हैं।

'ग्लोबल विटनेस' के अनुसार, भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों पर मनमाने आपराधिक आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है और उनके बैंक खाते फ्रीज़ कर दिए गए हैं, जिससे नागरिक समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट इस बात पर भी ज़ोर देती है कि कई देशों में पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ऐसे मुकदमों का सामना करना पड़ता है जिनका उद्देश्य ही जनहित में उठी आवाज़ों को रोकना है। ये मुकदमे इतने लंबे और खर्चीले होते हैं कि आम नागरिक उनमें फँसकर टूट जाते हैं या चुप हो जाते हैं।

आदिवासी समुदाय इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं कुल हत्याओं के 34 फीसदी शिकार आदिवासी रहे हैं। उनके पास कानूनी दस्तावेज़ों का अभाव, मुख्यधारा से दूरी और राजनीतिक समर्थन की कमी उन्हें कमजोर बनाती है, जबकि यही समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सहजीवन की मिसाल पेश करते आए हैं।

'ग्लोबल विटनेस' रिपोर्ट की भूमिका में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा लिखती हैं- 'हम केवल जलवायु आपातकाल के दौर में नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक प्रजातीय विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में ये पर्यावरण कार्यकर्ता उन चुनिंदा लोगों में हैं, जो इस लड़ाई में डटे हुए हैं। वे न केवल नैतिक दृष्टिकोण से सही हैं, बल्कि इसलिए भी सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि हमारी प्रजाति और हमारे हरित ग्रह का भविष्य उन्हीं के संघर्षों पर टिका है।'

आज जब जलवायु संकट के प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं- बाढ़, सूखा, जंगल की आग, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी- ऐसे समय में पर्यावरण रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट कुछ अहम सुझाव भी देती है - जैसे पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना, उनके खिलाफ दमनकारी मुकदमों को रोका जाना और जिम्मेदार कंपनियों की जवाबदेही तय करना, लेकिन यह तभी संभव है जब नागरिक समाज, मीडिया और आम जनमानस इन मुद्दों को अपने विमर्श के केंद्र में लाएं।

हाल ही में 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' (आईसीजे) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जलवायु संकट से निपटना सभी देशों की कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह फैसला बताता है कि अब जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून का भी गंभीर मुद्दा बन चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं। (सप्रेस)

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कटाक्ष

प्रीतम लखवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

भीड़ हमेशा ही भाड़ में जाती है

आमतौर पर मैं हमेशा ही भीड़ से बचता हूं। अक्सर ऐसे मार्ग का चुनाव करता हूं कि जहां पर अधिक मानव और वाहन न मिले। ताकि आसानी से मैं लक्षित गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकूं। महानगर में ऐसे मार्ग दिखाई नहीं देते। जिस ओर नजर जाती है इंसानों से ज्यादा तो वाहन नजर आते हैं। अगर वाहनों की जनगणना करवाई जाए तो नगर की जनसंख्या से 10 गुनी संख्या इनकी निकले।

खैर, भीड़ हमेशा शास्वत होती है। भीड़ आजकल सभी को पसंद है। खासकर नेतागिरी आरंभ कर रहे युवा नेता से लेकर सिद्ध हो चुके नेता तक को। भीड़ का अस्तित्व ही इनके लिए हुआ है और इंसानों का जन्म इस मृत्युलोक में भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। जिस नेता की रैली या सभा में जितनी अधिक भीड़ नजर आती है उसका प्रभाव उतना अधिक माना जाता है और उस नेता का भविष्य उतना ही उज्जवल माना जाता है।

नेता भीड़ जुटाने के लिए ऐसी-ऐसी तिकड़म भिड़ाते हैं कि भीड़ किसी चुंबकीय शक्ति की भांति खिंची चली आती है। इस भीड़ खिंचाव के लिए बाजार का भी भला होता है। कपड़ा बाजार हो या बर्तन बाजार या फिर अन्य कोई बाजार। यह सभी भीड़ के लिए सजग रहते हैं और यहीं से भीड़ को नियंत्रित करने के साजो-सामान जुटाने की पुरातन और आधुनिक परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा मनोविज्ञान कहता है। भीड़ में भांति-भांति के लोग भी शिरकत करते हैं। इतना ही नहीं पक्ष हो या विपक्ष।

इनकी रैली या सभाओं में भीड़ का चेहरा एक सा रहता है। बस उनके हाथों में झंडे बदल जाते हैं और यही झंडे तय करते हैं कि भीड़ का चेहरा एकमेव है यानि यह भीड़ अद्वैतवाद का प्रतीक होती है। यह सबके लिए, सबके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस भीड़ में से कोई एक ऐसा भी होता है जिसे मंच पर चढ़ जाने का मौका मिलता है या फिर विरोधी द्वारा चढ़ाया जाता है ताकी वह मंच से वह बोल दें, जिससे सामने वाले की मिट्टी पलीत हो जाए और विरोधी को विरोध का प्रसव हो जाए। बस! जब सबकुछ उनके मुताबिक हो जाता है तो रैली या आमसभा या पदयात्रा से भीड़ हमेशा भाड़ में जाने के लिए विवश कर दी जाती है। किसी ने ठीक कहा है कि लोकतंत्र को स्थायी रखने के लिए जिन जरूरी तंत्रों की आवश्यकता होती है। उसमें से एक भीड़ तंत्र भी है जो तब तक ही सम्मानीय है, जब तक रैली में कोई आभार न जता दे।

इसके बाद उसे वहीं भेज दिया जाता है, जिसे भाड़ कहा जाता है। वैसे भाड़ का चने से गहरा संबंध है, लेकिन चना भी भीड़ में भाड़ फोड़ता है। अकेला नहीं। इसलिए भीड़ और भाड़ का संबंध भी निरपेक्ष माना गया है। इधर, शहर में एक रैली आ रही है और पुलिस के जवान लाठी दिखाकर जनता को गली-कूचों से गुजरने पर बाध्य कर रहे हैं।

मैंने भी अपने वाहन का हैंडल उस इशारे की ओर मोड़ दिया, जिधर वाहनों की भीड़ गुत्थम-गुत्था हो रही थी। कुछ देर बाद यह भीड़ कहीं गुम हो गई और सुबह के अखबार में समाचार की सुर्खी बनकर इतरा रही थी।

गणेशोत्सव

योगेश कुमार गोयल

लेखक पत्रकार हैं।

10 दिनों का उत्सव इस बार 13 दिन तक क्यों?

गणेशोत्सव दस दिनों का क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें भारतीय ग्रंथों के गूढ़ संकेतों को जानना होगा। इस बार चतुर्थी से चतुर्दशी का अंतराल 13 दिनों का बन रहा है। यद्यपि परंपरा में 'दस दिन' मूल मंत्र है किन्तु अनंत चतुर्दशी का पूजन ही अंतिम है, इसीलिए भक्तों का उत्साह इस बार लंबे समय तक बना रहेगा। अब प्रश्न आता है कि इस बार उत्सव 10 के बजाय 13 दिनों का क्यों है। इसका उत्तर पंचांग और चंद्रगति की गणना में मिलता है। भारतीय कैलेंडर चंद्रमास पर आधारित है। कभी-कभी तिथियों के संयोग और क्रम बदलने से पर्व की अवधि बढ़ जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को थी जबकि अनंत चतुर्दशी 8 सितंबर को आएगी। इस प्रकार चतुर्थी से चतुर्दशी तक कुल 13 दिन का अंतराल है। यद्यपि धार्मिक परंपरा में गणपति की पूजा '10 दिन' ही मानी जाती है लेकिन इस बार भक्तों को उनकी उपस्थिति 13 दिनों तक अनुभव करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय संस्कृति की आत्मा उसके पर्व और उत्सवों में समायी हुई है। यहां प्रत्येक त्योहार केवल आस्था का अंग नहीं होता बल्कि जीवन, समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य बिठाने का माध्यम बनता है। इन्हीं में से एक है गणेश उत्सव। जिसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में बसे भारतीय बड़े उत्साह से मनाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला यह पर्व सामान्यत: दस दिन का होता है। परंतु इस वर्ष गणेश उत्सव दस दिनों के बजाय तेरह दिनों तक चलेगा। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब परंपरा 10 दिनों की है, तब इस बार 13 दिन क्यों? इसका उत्तर हमें गणेशोत्सव की गहन परंपरा, धार्मिक ग्रंथों और पंचांग गणना में मिलता है।

गणेशोत्सव दस दिनों का क्यों होता है, यह समझने के लिए हमें भारतीय ग्रंथों के गूढ़ संकेतों को जानना होगा। इस बार चतुर्थी से चतुर्दशी का अंतराल 13 दिनों का बन रहा है। यद्यपि परंपरा में 'दस दिन' मूल मंत्र है किन्तु अनंत चतुर्दशी का पूजन ही अंतिम है, इसीलिए भक्तों का उत्साह इस बार लंबे समय तक बना रहेगा। अब प्रश्न आता है कि इस बार उत्सव 10 के बजाय 13 दिनों का क्यों है। इसका उत्तर पंचांग और चंद्रगति की गणना में मिलता है। भारतीय कैलेंडर चंद्रमास पर आधारित है। कभी-कभी तिथियों के संयोग और क्रम बदलने से पर्व की अवधि बढ़ जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को थी जबकि अनंत चतुर्दशी 8 सितंबर को आएगी। इस प्रकार चतुर्थी से चतुर्दशी तक कुल 13 दिन का अंतराल है। यद्यपि धार्मिक परंपरा में गणपति की पूजा '10 दिन' ही मानी जाती है लेकिन इस बार भक्तों को उनकी उपस्थिति 13 दिनों तक अनुभव करने का अवसर मिलेगा। धार्मिक विद्वानों के अनुसार, यह कोई विरोधाभास नहीं है। गणेश जी की स्थापना चतुर्थी पर ही की जाती है और उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर ही होता है। इस बीच कितने दिन आते हैं, यह पंचांग की स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार 10 की बजाय 11 या 12 दिन भी हो सकते हैं। इस बार 13 दिनों की अवधि बनना भक्तों के लिए सौभाग्य का ही प्रतीक है। मानो यह विघ्नहर्ता का आशीर्वाद ही है कि उनका प्रवास इस बार और लंबा होगा। यदि दस दिन आत्मशुद्धि की साधना के हैं तो अतिरिक्त तीन दिन 'अनंत' का आशीर्वाद हैं।

संख्या 'दस' हमारे जीवन और ब्रह्मांड से गहरे रूप में जुड़ी है। हिन्दू दर्शन में दस दिशाओं का वर्णन है, दस इंद्रियां कही गई हैं और दस अवतारों की परंपरा आती है। संख्या दस का अर्थ है संपूर्णता। दस दिशाएं, दस इंद्रियां और दशावतार, ये सभी जीवन और ब्रह्मांड की पूर्णता का संकेत हैं। संख्या दस संपूर्णता और पूर्ण चक्र का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर दस दिनों तक की पूजा यही दर्शाती है कि जीवन की सभी इंद्रियों, दिशाओं और गुणों को संयमित करके अंतत: आत्मा को शुद्ध कर लिया जाए। दस दिनों में प्रत्येक दिन साधना का एक चरण है, कहीं संयम, कहीं विनम्रता, कहीं धैर्य, कहीं ज्ञान, कहीं परिवार और परंपरा का सम्मान। अनंत चतुर्दशी को विसर्जन का विधान इसीलिए रखा गया कि दस दिन की साधना पूरी होने के बाद जीवन की अस्थिरता और अनित्यता की शिक्षा भी स्मरण हो। इस दस दिवसीय आयोजन के पीछे महाभारत से जुड़ी एक कथा भी कही जाती है। व्यास ऋषि ने जब महाभारत की रचना का संकल्प लिया, तब उन्होंने गणपति से इसे लिपिबद्ध करने का निवेदन किया। गणेश ने इसे स्वीकार किया पर यह शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास ने यह कहा कि वे श्लोक तभी लिखेंगे, जब उन्हें उसका अर्थ समझ आए। इस प्रकार लेखन का कार्य शुरू हुआ और लगातार दस दिनों तक गणपति बिना रुके लिखते रहे। दसवें दिन यह कार्य पूर्ण हुआ और तब गणेश को जल स्नान कराया गया। यही कथानक भी दस दिनों के उत्सव का एक आधार माना जाता है। गणेश जी का स्वरूप और उसमें छिपी शिक्षाएं भी दस दिनों की साधना को गहन बनाती हैं। उनका बड़ा मस्तक हमें बुद्धि और विवेक की ओर प्रेरित करता है। छोटे नेत्र ध्यान और एकाग्रता का महत्व बताते हैं। विशाल कान धैर्य का संदेश हैं जबकि छोटा मुख संयम और अल्पभाषिता की शिक्षा देता है। हाथी का सिर शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है तो उनका वाहन मूषक विनम्रता और लघुता में भी सामर्थ्य की व्याख्या करता है। इन प्रतीकों का चिंतन और आत्मसात दस दिनों तक किया जाता है, जिससे साधक का जीवन संतुलन और ज्ञान से भर उठ करता है।

गणेशोत्सव केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनचेतना का माध्यम बनाया। ब्रिटिश शासन में जब सामूहिक आयोजन वर्जित थे, तब तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन आरंभ किए, जिससे समाज में एकता, भक्ति और राष्ट्रप्रेम का समन्वय हुआ। आज भी पंडालों में सामूहिक आरती, दान और सेवा गतिविधियां इसी सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाती हैं। यह पर्व लोगों को एक साथ लाता है, जाति-पाति के भेदभाव को खो देता है और 'एकता ही शक्ति है' का वास्तविक संदेश देता है। उपनिषदों और वेदांत के दृष्टिकोण से देखें तो विसर्जन का महत्व और भी गहरा है। मिट्टी की प्रतिमा 10 या 13 दिनों तक पूजित होकर अंतत: जल में प्रवाहित हो जाती है। यह सृष्टि के उसी नियम का स्मरण है, जिसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में आता है 'यथा सोम्यैकेना मृद्रवेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं' अर्थात् जैसे मिट्टी को समझने से मिट्टी से बने सब रूपों को समझा जा सकता है। विसर्जन केवल मूर्ति का जल में जाना नहीं बल्कि यह जीवन और मृत्यु का गहन संदेश है। जैसे मिट्टी की प्रतिमा 10-13 दिन तक पूजित होकर अंतत: उसी मिट्टी में विलीन हो जाती है, वैसे ही यह संसार है। विसर्जन हमें यही सिखाता है कि नाम और आकार नश्वर हैं पर मूल तत्व शाश्वत है। गणेश उत्सव इस दार्शनिक गहराई का उत्सव है। 10 दिनों का इसका महत्व सनातन है पर जब पंचांग की गति इसे 13 दिन का बना दे तो हमें इसे और अधिक आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए।

विघ्नहर्ता इस बार अपने भक्तों के बीच अधिक समय रहेंगे, अधिक अवसर मिलेंगे भक्ति और सेवा के कार्यों में जुटने के, और अधिक समय तक सामूहिक मेलजोल और उत्साह का अनुभव होगा। कुल मिलाकर, यही कहा जा सकता है कि गणेश चतुर्थी का दस दिन का महोत्सव जीवन के संतुलन, साधना, ज्ञान और विघ्न निवारण का प्रतीक है। इस वर्ष जब यह काल बढ़कर तेरह दिन का हो रहा है तो यह हमारे लिए विशेष अवसर है। हमें इसे समय की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इन अतिरिक्त दिनों में और भी अधिक साधना, सेवा और सामूहिकता का भाव अपनाना चाहिए। गणपति बप्पा का यही संदेश है कि जीवन में विघ्न कितने ही बड़े क्यों न हों, धैर्य, ज्ञान और एकता से उन्हें पार किया जा सकता है और जब भक्ति सच्ची हो तो गणेश का आशीर्वाद समय की परिधि से भी परे होकर अपना विस्तार करता है। यही इस वर्ष के 13 दिवसीय गणेशोत्सव का सबसे बड़ा संदेश है।

मानसिक स्वास्थ्य

डॉ. सत्यकांत चतुर्वेदी

लेखक प्रख्यात मनोचिकित्सक हैं।

समाज के लिए चेतावनी है देवास की घटना

यह समय है कि हम केवल बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद पर नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। उन्हें सुनना, उनके साथ समय बिताना, गुस्से को सकारात्मक ढंग से व्यक्त करना सिखाना और हिंसा से दूर रखना - यह परिवार और समाज की साझा ज़िम्मेदारी है। इस खबर से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम बच्चों के मन और रिश्तों को नहीं समझेंगे तो छोटी-सी अनदेखी बड़ी त्रासदी बन सकती है।

देवास में नाबालिग भाईयों ने मिलकर चचेरे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को हार्वेस्टर के नीचे छिपा दिया और सबूत मिटाने के लिए नहा लिया। मार्च से मृतक वेदांश और 11 साल के आरोपी के बीच विवाद चल रहा था। इसी बात से नाराज आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। देवास की घटना बेहद दर्दनाक है और हमें समाज के लिए चेतावनी भी देती है। जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह केवल अपराध नहीं, बल्कि कई स्तरों पर पनपती समस्याओं का परिणाम दिखती है।

मनोवैज्ञानिक कारण

इस उम्र के बच्चों में गुस्सा और आक्रोश भी को संभालने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती। यदि बच्चा लंबे समय तक उपेक्षा, ईर्ष्या, असुरक्षा या हीनभावना का अनुभव करता है तो वह छोटे-छोटे विवादों को भी जीवन-मरण का सवाल समझने लगता है। हिंसा देखकर बड़े होने वाले बच्चे यह मान लेते हैं कि समस्या का हल बातचीत से नहीं, बल प्रयोग से होता है।

सामाजिक कारण

परिवार और समाज बच्चों के लिए पहला विद्यालय हैं। अगर घर में संवाद का अभाव है, माता-पिता व्यस्त हैं, निगरानी कम है या बच्चों को सकारात्मक आदर्श नहीं मिलते, तो वे गुस्से और आक्रोश को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। डिजिटल मीडिया और फिल्मों में दिखने वाली हिंसा भी संवेदनशील उम्र में आक्रामकता को और मजबूत कर देती है।

जैविक पहलू

हालाँकि जैविक स्तर पर किशोर मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी परिपक्व नहीं होता, जिससे आवेग पर नियंत्रण कमजोर रहता है। पर असली खतरा तब बढ़ता है जब यह कमजोरी असुरक्षित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक माहौल से जुड़ जाती है।

यह समय है कि हम केवल बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद पर नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। उन्हें सुनना, उनके साथ समय बिताना, गुस्से को सकारात्मक ढंग से व्यक्त करना सिखाना और हिंसा से दूर रखना - यह परिवार और समाज की साझा ज़िम्मेदारी है। इस खबर से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम बच्चों के मन और रिश्तों को नहीं समझेंगे तो छोटी-सी अनदेखी बड़ी त्रासदी बन सकती है।

संवाद

संजय तेलंग

(वरिष्ठ पत्रकार और लेखक)

स्थानीय भाषा और बोली में है संप्रेषण की क्षमता

इलाका बदलने का अंदाजा वहां की भाषा से होता है। प्रदेश ही नहीं, जिलों की भाषा में भी फर्क आता है। राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में तो स्थानीय भाषाओं के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे ही आप एक अंचल से दूसरे अंचल में प्रवेश करते हैं, भाषा में बदलाव दिखाई देने लगता है। बोलने का तरीका भी बदल जाता है। मुम्बईया बोली का अपना अलग अंदाज है, जो हिंदी फिल्मों से खूब प्रचार पा चुका। अपनी बात को सरल तरीके से कहने और समझाने के लिए स्थानीय बोलियां जन्म लेती हैं। सुविधा और जरूरत के अनुसार इनमें शब्दों का विस्तार होता चला गया और स्थानीय बोली चलन में आती गई।

दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं का अपना महत्व है। बात स्थानीय भाषाओं (लोकल लैंग्वेज) की करें तो इनके महत्व को भी कम करके नहीं आका जा सकता है। दरअसल, भाषाओं का मूल उद्देश्य है संप्रेषण, यानी विचारों का आदान-प्रदान। स्थानीय भाषाएं, जिन्हें स्थानीय बोली कहना सही होगा, भी संप्रेषण का ही काम करती हैं, और विचारों को आसानी से आदान-प्रदान करने में सक्षम होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें वह मान्यता नहीं मिल पाती, जो किसी समृद्ध भाषा को मिल जाती है। स्थानीय भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले शब्द कभी-कभी हास्य भी उत्पन्न करते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य हास्य पैदा करना कदापि नहीं होता। दरअसल, स्थानीय भाषा/ बोली न जानने वालों के लिए कुछ शब्द अजीब होने से हास्य का विषय बन जाते हैं। एक बार में बस में सफ़र कर रहा था। बस में मोबाइल पर किसी से चर्चा कर रहा एक ग्रामीण सिग्नल न मिलने से परेशान हो रहा था। फोन बार-बार कट रहा था, तभी उसने झुंझला कर सामने वाले से कहा-मैं बाद में बात करता हूं, अभी फोन 'छोड़-पकड़' कर रहा है। 'छोड़-पकड़' का उपयोग उसने सिग्नल न मिलने के लिए किया था। इसे स्थानीय भाषा उदाहरण कह सकते हैं। यदि वह यात्री शहरी इलाके में इन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो उसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए विस्तार से बताना होगा।

ऐसा ही एक और उदाहरण पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में सामने आया। तेज बारिश हो रही थी, कुछ लोगों के साथ मैंने भी एक टापरी के नीचे शरण ले रखी थी। काफी देर तक बारिश नहीं थमी तो पास खड़े एक सज्जन ने किसी को फोन मिलाया और कहने लगे-बारिश 'आऊं-जाऊं' कर रही है, पूरी रुके तो निकलूं। उनके कहने का आशय था बारिश कभी थम जाती है, कभी होने लगती है, पूरी तरह रुकने पर ही निकल सकूंगा। वैसे तेज बारिश के लिए अनेक स्थानों पर झमाझम और रिमझिम बारिश के लिए फुरफुरी शब्दों का उपयोग भी किया जाता है, विशेष रूप से मालवा और निमाड़ अंचल में। स्थानीय भाषा में उपयोग होने वाले बहुत से शब्द शहरी लोगों के लिए हास्य का विषय बन जाते हैं।

इंदौर की भाषा मूल रूप से हिंदी है, वैसे अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाएं भी यहां बोली जाती हैं। मालवा अंचल का शहर होने से यहां मालवी बोलने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। मालवी की अपनी मिठास है, जो इसे बोलने, सुनने और उपयोग करने वाले ही जानते/ समझते हैं। बावजूद इसके इंदौरियों की अपनी अलग जुबान या बोली भी है। सोशल मीडिया पर इस बोली में बनी रील्स खूब वायरल्स हो रही हैं। अपनी सुविधा से गढ़ी गई यह बोली हास्य का विषय बन गई है। 'आ रिया हूं भिया, जा रिया हूं भिया, जराक सा टेम नी है, जरा कने आना' जैसे शब्दों का ठेठ इंदौरी भरपूर उपयोग करते हैं। जब दो ठेठ इंदौरी आपस में बात करते हैं, तो उन्हें इस बात का बिलकुल भी अहसास नहीं होता कि उनका वार्तालाप बाहर के किसी व्यक्ति के लिए हास्य का विषय बन गया है।

राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में तो स्थानीय भाषाओं के एक से एक उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे ही आप एक अंचल से दूसरे अंचल में प्रवेश करने लगते हैं, भाषा/ बोली में बदलाव तो दिखाई देने लगता है, साथ ही बोलने का तरीका भी बदल जाता है। मुम्बइया बोली का भी अपना अलग अंदाज है, जो हिंदी फिल्मों से खूब प्रचार पा चुका है। सही बात तो यह है कि भाषा की तरह ही अपनी बात को सरल तरीके से कहने/ समझाने के लिए स्थानीय भाषाएं/ बोलियां जन्म लेती हैं। आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इनमें शब्दों का विस्तार होता चला जाता है और अंतत: स्थानीय भाषा/ बोली चलन में आ जाती है।

भाषा की उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों में एक सांकेतिक भाषा सिद्धांत भी है, जो यह कहता है कि भाषा की शुरुआत इशारों से हुई। इशारों में भी बहुत ताकत होती है, इशारों में कई बार वह बात भी समझाई जा सकती है, जिसके लिए जुबान कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस सिद्धांत के उदाहरण हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे किसी बात से इनकार के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर को दोनों ओर हिलाकर अपनी बात समझाई जा सकती है। किसी बात से सहमत होने पर सिर को ऊपर-नीचे कर सहमति जताई जा सकती है, इसके लिए जुबान को हां कहने की जरूरत नहीं है। किसी को पास बुलाना है तो सिर को ऊपर-नीचे कर या हाथ हिलाकर यह काम बखूबी किया जा सकता है। स्थानीय भाषा / बोली हो या इशारे सभी का उद्देश्य अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना और उसकी बात समझना ही है, यदि यह उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो इसमें बुरा क्या है! रही बात इससे हास्य उपजने की, तो दोनों पक्ष किसी तरह का बुरा भी नहीं मानते। अपनी भाषा या बोली का उपयोग करने में कैसी शर्म या झिझक। यही सोच कर वे बिंदास अपने मन की भाषा का उपयोग करते हैं, किसी को उनकी बातों पर हंसी आए तो आती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

Mantra of Success

राजेश शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
मोटिवेशनल स्पीकर

हौसलों की उड़ान - एजुकेट गर्ल्स बनी 2025 रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड पाने वाली पहली भारतीय संस्था

दो करोड़ से ज़्यादा बेटियों को स्कूल लौटाने की सामुदायिक पहल रंग लाई , मिला एशिया का नोबेल पुरस्कार

एशिया का सर्वोच्च सम्मान रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इस अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड हासिल कर पहली भारतीय संस्था बनने का गौरव प्राप्त एजुकेट गर्ल्स इन दिनों देश और दुनिया में सुर्खियों में है। 'मीलों लंबे सफर की शुरुआत महज छोटे - छोटे कदमों से होती है 'इसे साकार किया है एजुकेट गर्ल्स ने। सबसे दूरदराज़ गांव की एक बच्ची से शुरू हुई यह मुहिम अब लाखों बिटियाओं की ज़िंदगी बदल चुकी है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को जमीन पर उतार कर उन्हें साकार कर एजुकेट गर्ल्स आज हम सब के समक्ष नजीर बनी हुई है। 2007 में बनी एजुकेट गर्ल्स अब तक 30 हज़ार से ज़्यादा गांवों में काम कर चुकी है। 55,000 से अधिक

सामुदायिक वालंटियर्स की मदद से इसने 20 लाख से ज़्यादा बच्चियों को स्कूल वापिस लाने और 24 लाख से अधिक बच्चों की बेहतर पढ़ाई में मदद दी है। लक्ष्य है कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुँचा जाए और शिक्षा के जरिए ग़रीबी और अशिक्षा के चक्र को तोड़ा जाए।

एजुकेट गर्ल्स राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसका काम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। 2007 से अब तक, संस्था ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के 30 हज़ार से अधिक गांवों में 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों का स्कूल में दाखिला करवाने मे मदद की है।

एजुकेट गर्ल्स क्यों है चर्चाओं में

एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से सम्मानित किया गया हैं। एशिया का यह सर्वोच्च सम्मान पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिला है। यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को बालिकाओं और युवतियों की शिक्षा के समाज की अतार्किक सांस्कृतिक धारणाओं को चुनौती देने, उन्हें निरक्षरता से मुक्त करने और उन्हें कौशल, हिम्मत और आत्मनिर्भरता देने के लिए दिया गया है। अब एजुकेट गर्ल्स का नाम उन महान हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है, जिनमें सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर टेरेसा और ऑस्कर विजेता हायाओ मियाज़ाकी जैसे दिग्गज शामिल हैं।

एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सेफीना हुसैन ने कहा –यह हमारे लिए और भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। यह सम्मान भारत के उस जन-आंदोलन जैसी मुहिम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है, जो सबसे दूरदराज़ गांव की एक बच्ची से शुरू हुई और अब लाखों बच्चियों की ज़िंदगी बदल चुकी है। यह अवॉर्ड हमारे समर्पित टीम बालिका वालंटियर्स, साझेदारों, समर्थकों और सबसे बढ़कर उन लाखों बच्चियों के नाम है, जिन्होंने अपना हक 'शिक्षा' वापस पाया। अगले दस सालों में हम एक करोड़ से भी ज़्यादा शिक्षार्थियों तक पहुँचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और भारत के इस मॉडल को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी साझा करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि जब एक लड़की पढ़ती है, तो वह कई औरों को साथ लेकर आगे बढ़ती है और पूरे समाज में बदलाव लाती है।

एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने कहा– हमारे लिए शिक्षा सिर्फ़ विकास का साधन नहीं, बल्कि हर लड़की का बुनियादी अधिकार है। यह सम्मान बताता है कि जब सरकार, कॉरपोरेट, परोपकारी संस्थाएं और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो गहरी सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियों को बदला जा सकता है। हम भारत सरकार के प्रयासों और सहयोग के लिए आभारी हैं, जिन्होंने इस मिशन को संभव बनाया। साथ ही, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो विलनुएवा को भी हार्दिक बधाई, जिनके काम ने हम सभी को प्रेरित किया है।

रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने साहस और नयेपन के साथ समाज में गहरा बदलाव लाने का काम किया हो। इस साल भारत की एजुकेट गर्ल्स के साथ मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एल. विलनुएवा को भी यह पुरस्कार मिला है।

सफ़ीना हुसैन ने एजुकेट गर्ल्स से भारत की गौरव पताका दुनिया भर में फहराई–सामाजिक प्रभाव की अग्रणी, सफ़ीना हुसैन, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक और बोर्ड सदस्य हैं। यह एक भारतीय गैर-लाभकारी संस्था है जो भारत के कुछ सबसे दुर्गम गाँवों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में, उनके निरंतर कार्य के सम्मान में, सफ़ीना को लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। यह 2023 में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि में और इजाफा करता है, जब वह ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा में उनके योगदान के लिए WISE पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

सफ़ीना के मार्गदर्शन में, एजुकेट गर्ल्स शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए नवीन वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, विश्व स्तर पर एक अग्रणी शक्ति बन गई है। उनके नेतृत्व में, एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, एक परिणाम-आधारित वित्तपोषण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने सीखने और नामांकन दोनों में असाधारण परिणाम प्राप्त किए। उन्होंने एजुकेट गर्ल्स को एशिया का पहला TED ऑडेसियस प्रोजेक्ट बनने में मदद की, जो दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों के समाधानों को बढ़ाने पर केंद्रित एक सहयोगी वित्तपोषण पहल है।सफीना को नीति आयोग महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यूएसएआईडी मिलेनियम अलायंस पुरस्कार, एमआईटी सॉल्व्स लर्निंग फॉर गर्ल्स एंड वीमेन चैलेंज, सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल पुरस्कार और विश्व बैंक इंडिया डेवलपमेंट मार्केटप्लेस पुरस्कार सहित कई वैश्विक सम्मान प्राप्त हुए हैं। सफीना नई दिल्ली में पली-बढ़ी हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पूर्व छात्रा हैं।

वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन

जैसे ही गठबंधन टूटेगा, सरकार धड़ाम से गिर जाएगी : जीतू पटवारी

बैतूल। जिले की सियासत में बुधवार को कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बैतूल पहुंचकर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान पटवारी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि वोट चोरी में पहले कई प्रदेशों में एक भी विधायक भाजपा का नहीं था। चुनाव में वहां पर भाजपा की सरकार बन गई। विधायकों को आपने चुना और उन्हीं विधायकों ने जाकर सरकार बना ली, तो आपके वोट का क्या महत्व। वोट की ताकत नहीं बचेगी, तो तानाशाही आएगी, इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। पांच लाख नौकरी देने का प्रधानमंत्री का वादा झूठा निकला और अब

चोरी से सरकार बनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार बैशाखी है, पर जैसे ही गठबंधन टूटेगा, सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। यह बात उन्होंने शिवाजी आडिटोरियम में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसके बाद सभी कांग्रेसी, रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए थे। सभा स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि तासी कंजेंवेशन बनने से हमारे दस गांव जा रहे हैं। इससे जिले को फायदा होने की जगह आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। भाजपा में चाल, चरित्र के आधार पर श्रेय लेने की होड़ मची है। इसी वजह जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि जिले में न तो कोई बड़ा कारखाना है और न कोई बड़ा शिक्षण संस्थान है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विभाग में कमीशन बाजी चल रही है और दूसरी ओर किसान खाद-बीज, यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। कांग्रेसियों ने बड़ी रैली निकालकर पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सोफा और इसके पश्चात शाम साढ़े पांच बजे बैतूल गंज स्थित कांग्रेस कार्यालय का भी उद्घाटन किया प्रदेश कार्यालय से पधारे नेताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दिगंबर जैन समाज के पर्यूषण पर्व के सातवें दिन को उत्तम तप धर्म दिवस के रूप में मनाया

पर्व के दिनों में श्रद्धालु तप आराधना उपवास की तपस्या कर रहे हैं

धार। दिगंबर जैन समाज के पर्यूषण पर्व के सातवें दिन को उत्तम तप धर्म दिवस के रूप में मनाया गया। पर्व के दिनों में श्रद्धालु तप आराधना उपवास की तपस्या कर रहे है। जैन धर्म में उत्तम तप धर्म दस परम गुणों (दशलक्षण धर्म) में से एक है, इसका अर्थ है कर्मों की निर्जरा करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर, वाणी और मन को अनुशासित करना। इसमें आंतरिक तप (अंतरंग तप) पर ज़ोर दिया जाता है, जो सच्ची श्रद्धा और अहिंसा के साथ किया जाता है, न कि

शरीर को नुकसान पहुँचाने पर। 10 लक्षण पर्व पर समोसरण विधान का आयोजन गुरुदेव के गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है जिसके मुख्य पात्र चक्रवर्ती श्री राजेंद्र जी लक्ष्मी जी बांझल है।

आज उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर मुनिराज ससंघ के सानिध्य में श्रीजी का अभिषेक और शांति धारा के साथ दिन की शुरुआत हुई। पर्यूषण महापर्व के सातवें दिन प्रातः मंदिर जी में श्रीजी के अभिषेक शांतिधारा मे आज विद्वान विधानाचार्य पंडित भरत शास्त्री के मार्गदर्शन में भगवान विराजमान कर प्रथम अभिषेक करने के लाभार्थी सतीश युगांक लुहाडीया परिवार को सौभाग्य मिला। समवशरण मंडल विधान रचना के समक्ष उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के सानिध्य में आज के अभिषेक एवं शांतिधारा के लाभार्थी परिवार मंडल विधान के मुख्य पात्र चक्रवर्ती राजेन्द्र बांझल, नरेश गंगवाल, संजय छाबड़ा, नरेंद्र काला परिवार। वही श्रीजी पर अभिषेक के पूर्व रत्नवृष्टि की गई। आज उत्तम तप धर्म के दिन दीप प्रज्वलन गुरु पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट करने के लाभार्थी कुसुमलता, राजेंद्र, श्रीमती लक्ष्मी बांझल परिवार थे। समवशरण मंडल से गुरुदेव ने अपनी अमृतमयवाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित किया। कल सुगंध दशमी के पावन अवसर पर धार समाज द्वारा एक बस तीर्थ यात्रा के लिए निकाली गई। धार से कागदीपुरा, अनारद, आहू तीर्थ, मानतुंगगिरी पर धूप खेवन का कार्य कर पुनः धार दिगंबर जैन मंदिरजी में आकर धूप खेवन , सामयिक किया। संध्याकालीन पंच परमेष्ठी समवशरण की आरती गुरुदेव की आरती श्रद्धालुओं के द्वारा की गई। तत्पश्चात धार्मिक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें कई पुरस्कार दिगंबर जैन महिला मंडल के द्वारा दिए गए। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल द्वारा दी गई।

नपा मुलताई बस स्टैंड दुकान की खोलेगी सील

दुकानों के मूल्य वृद्धि का मामला होगा परिषद में तय

बैतूल/मुलताई। नगरपालिका द्वारा बस स्टैंड दुकानों के किराए में की गई वृद्धि, दिए गए नोटिस एवं दुकानें सील किए जाने को लेकर बस स्टैंड व्यापारियों में भारी रोष है। आज बस स्टैंड व्यापारियों ने संजय यादव, महेश पाठक, सुमित शिवहरे, अनिल सोनी के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका के व्यापारियों के प्रति व्यवहार पर विरोध जताया इसके बाद नगर पालिका सभा कक्ष में व्यापारियों एवं नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी के बीच हुई चर्चा में यह तय किया गया कि हाल ही में सील की गई दुकान का ताला तत्काल नगर पालिका खोलेगी साथ ही मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को परिषद बैठक में रखा जाएगा जीसके बाद परिषद के निर्णय के अनुसार किराया वृद्धि तय कर लागू की जाएगी। इस प्रकार अब मूल्य वृद्धि की गेंद पार्षदों के हाथ है और यह देखना रोचक होगा कि जनता से चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि अपना क्या रुख अख्तियार करते हैं। नई दर लागू होने के बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी नगर पालिका पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि मनमानी ढंग से मूल्य वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है यह मूल्य वृद्धि व्यापारियों के लिए बड़ा संकट साबित होगी।

भाजपा ने सेवा कार्य कर मनाया प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन

अस्पताल में किया फल वितरण, असहायों को कराया भोजन फिर किया पौधा रोपण

बैतूल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के जन्म दिवस पर जिला भाजपा परिवार ने सेवा कार्य कर मनाया। इस कड़ी में सुबह जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करने के पश्चात दोपहर को दीनदयाल रसोई में असहाय लोगों को भोजन करवाने के बाद बैतूल गंज मंडल के रामनगर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि हमारे नेता हेमंत खंडेलवाल जनसेवा को ही सर्वोत्तम नीति मानते है इसलिए उनके जन्मदिन पर विभिन्न मंडलों में सेवा कार्य के रूप में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय राज्यमंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके ने कहा कि भाजपा परिवार के लिए सेवा साधना की तरह होती है, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ कार्य करते है। उनके प्रेरणादायी व्यक्तित्व से

कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वहीं आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सादा जीवन उच्च विचार के राजनीति में विरले उदाहरण है और आज उनके जन्मदिन पर सेवा कार्य हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लिए शुभ अवसर है। इस अवसर पर जिला महामंत्री कमलेश सिंह, कृष्णा गायकी, डा.महेंद्रसिंह चौहान, उपाध्यक्ष नरेश फाटे, नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश मेंबर राजा साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नेहरू पार्क की दुकानों का बराबर पार्टीशन कर किया जाएगा शेड निर्माण

चौपाटी का 1.70 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण

बैतूल। नगरपालिका महानगरों की तर्ज पर शहर की चौपाटी का सौंदर्यीकरण करवाएगी और यहां संचालित 125 दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। पार्टीशन करके सभी दुकानों को अलग-अलग किया जाएगा। दुकानों के ऊपर शेड डालकर दुकानों के सामने फाइबर और स्टील की डिजाइन लगाई जाएगी, ताकि दुकानें अव्यवस्थित ना लग सकें। दरअसल शहर के नेहरू पार्क के पास चौपाटी स्थित है, यहां कई दुकानदार चाट, आईस्क्रीम सहित विभिन्न प्रकार की चटपटी खाद्य चीजों की दुकाने लगाते है। प्रतिदिन यहां सुबह और शाम के समय भारी संख्या में लोग पहुंचते है। इस चौपाटी की रंगत बदलने नगरपालिका ने योजना बनाई है, जिसके लिए 1 करोड़ 70 लाख की डीपीआर बनाई थी। जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद इसके टेंडर किए थे। टेंडर ओपन होने के बाद ठेकेदार को जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। बताया गया कि यह प्रोजेक्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल और

नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर के प्रयासों से शुरू होगा और इसका लाभ दुकानदारों के साथ-साथ आमजनों को भी मिलेगा।

अभी चौपाटी पर दुकानों का एक समान नहीं है साइज– नेहरू पार्क पर लंबे समय से चौपाटी लग रही है। यहां दुकानों के साइज एक समान नहीं है, जिससे अव्यवस्थित दुकानें लगने से यहां आने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। लेकिन अब चौपाटी के सौंदर्यीकरण के बाद यहां पर फाइबर और एल्यूमीनियम से शेड का निर्माण सडक़ किनारे दोनों साइड दुकानों के ऊपर किया जाएगा। इसके बाद सभी दुकानें एक साइज की रहेंगी। दुकानों का अलग-अलग पार्टीशन होगा, ताकि दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। जहां पर दुकानें लगाई जाएंगी, वहां पर फ्लोर बनाया जाएगा। इससे दुकानदारों के अलावा ग्राहकों को भी परेशानी नहीं होगी।

पाथ-वे के साथ लैंप लाइट लगेंगे – वर्तमान में चौपाटी पर लगने वाली 125 दुकानें अव्यवस्थित लग रही है। यहां पर आए दिन जाम के हालात बनते हैं। चौपाटी के बीच व्हाइट टॉपिंग सडक़ का निर्माण भी चल रहा है। व्हाइट टॉपिंग सडक़ के बाजू में पाथ-वे का भी निर्माण होगा। इससे इस मार्ग पर आने वाले जाने में भी आसानी होगी। दुकानों के अंदर लैंप वाले लाइट लगाए जाएंगे। जिससे यहां आने वाले लोगों को महानगरों की तर्ज पर चौपाटी का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस कार्य के टेंडर तो हो चुके है, लेकिन अभी वर्क आर्डर जारी नहीं किये है। जैसे ही वर्कआर्डर जारी होगे, काम भी तेजी से शुरू कर दिया जायेगा।

इनका कहना है -

नेहरू पार्क की चौपाटी का सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर हो गए हैं। ठेकेदार से जल्द ही एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। 125 दुकानों को दोनों ओर पार्टीशन, फाइबर और एल्यूमीनियम के शेड बनाकर व्यवस्थित किया जाएगा।

- सतीश मटसेनिया,
सीएमओ, नपा बैतूल

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' भेंट की।

माँ तुझे प्रणाम योजनान्तर्गत प्रतिभागियों का दल रवाना

हरदा (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल द्वारा मां तुझे प्रणाम योजनान्तर्गत नर्मदापुरम संभाग से हरदा, रायसेन एवं नर्मदापुरम की एन.सी.सी, स्काउट, खेल, मेधावी, तथा सामाजिक कार्यकर्ता वर्ग में चयनित 50 प्रतिभागियों को मांडू, ओम्कारेश्वर व महेश्वर तक राज्य के विभिन्न पुरात्व धरोहर, भौगोलिक, दर्शनिक एवं धार्मिक प्राचीन स्थलो का भ्रमण कराया जायेगा। जिला खेल अधिकारी सुश्री उमा पटेल ने बताया कि सोमवार को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय से सांसद प्रतिनिधि श्री मनोज शर्मा, संस्था की प्राचार्या सुश्री कामिनी जैन, विधायक प्रतिनिधि श्री रमेश उपरारियां, संस्था के स्पोर्ट्स अधिकारी श्री धर्मेंद्र गुर्जर ने जिले के प्रतिभागियों को खेल प्रशिक्षक श्री आस्कर मोजिस, ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान, सुश्री उपासना ठाकुर, सुश्री आरती शर्मा, सुश्री शशि रघुवंशी के साथ दल को रवाना किया। यह दल 1 से 5 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश श्री रघुवंशी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया

हरदा (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद रघुवंशी ने सोमवार को जिला जेल, हरदा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने जिला जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक एवं पुरुष व महिला बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाएं रसोई घर, पीने के पानी, बैरकों में साफ-सफाई, बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, भोजन व्यवस्था का भी जायजा लिया व आवश्यक निर्देश प्रदान किए ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से नई दिल्ली में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य भेंट की।

भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक चरित्र समावेशी है : अम्बिका दत्त शर्मा

कोलकाता। साल्ट लेक स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद,(ICPR) नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्शन विषय पर दो दिवसीय 28-29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय दर्शन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अम्बिका दत्त शर्मा ने अपने बीज वक्तव्य में कहा कि हम अपनी ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार कर रहे हैं, ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कर का लक्ष्य होता है अपनी सामुदायिक अस्मिता को अंगीकार करना। भारत में यदि हम अपने ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कर में थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में पुनराविष्कर का पवित्र लक्ष्य कहीं पहचान की राजनीति की शिकार न हो जाये इसे देखना जरूरी है।

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में संयोजक व क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता के प्रभारी डॉ अमित राय ने स्वागत वक्तव्य में भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान के दर्शन की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए भारतीय तर्क प्रणाली और पश्चिमी तर्क प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्वों को बताया। उन्होंने विज्ञान के सापेक्षता और पारस्परिकता के नियम की व्याख्या करते हुए मानव, प्रकृति और समाज के अंतरसंबंधों को समझने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि भारतीय धर्म संसद के अध्यक्ष बिट्ठलदास मूंधड़ा ने विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों की ऐतिहासिक परंपरा की चर्चा करते हुए विज्ञान के दर्शन के ऐतिहासिक विकास यात्रा को विस्तान से बताया और भविष्य की ज्ञान परंपरा की ओर संकेत किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.नवीन चंद्र लोहानी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न तत्वों को पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर जोर दिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके प्रावधान होने की जानकारी दी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि के अनुवाद विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर हनुमानप्रसाद शुक्ल ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ केवल पश्चिम की दृष्टि नहीं है। हमारे यहां ब्रह्म तत्वों का साक्षात्कार वैदिक ऋषि करते आये हैं और वे परम तत्व के प्रखंड तत्व को ब्रह्म को ही ज्ञान कहते हैं और विज्ञान ज्ञान का विभक्तिकरण है विज्ञान पहले उसे हिस्सों में बांटकर देखता है और फिर उनके योग में उसे अखंड की कल्पना करता है। वैदिक ऋषियों ने पहले सत्य का शब्द का प्रयोग किया,भारतीय ऋषियों की उस अखंड सत्य को एक साथ देख पा लेने की विकलता या जिज्ञासा है। धन्यवाद ज्ञापन कोलकाता केंद्र की सहायक प्रोफेसर डॉ.चित्रा माली ने किया। उद्घाटन सत्र का संचालन एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.अमरेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।

प्रथम अकादमिक सत्र 'भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्व का विचार' के वक्ता डॉ.आशुतोष व्यास ने भारतीय दर्शन में शब्द-ब्रह्म और नारदीय सूक्त का उल्लेख करते हुए कहा कि 'जैसे ही जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही ज्ञाता और ज्ञेय के बीच भेद पैदा होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस भेद को श्रुति, युक्ति और अनुभव के माध्यम से पाटने का प्रयास करती है। यही समग्रता हमारी विशिष्टता है'।

प्रियंकर पालीवाल ने भारतीय परंपरा की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को पश्चिम के संदर्भ में रेखांकित किया। उनके वक्तव्य में नैतिकता, संवेदना और मूल्यबोध पर जोर रहा। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने विज्ञान और धर्म के रिश्ते पर स्वामी विवेकानंद के विचार के आधार पर तर्कसंगतता,परीक्षण, अनुभव,समावेशिता सभ्यता, संस्कृति, और भाषा का ऐतिहासिक विस्तार, डीकॉलोनाइजेशन और डीमिस्टिफिकेशन की आवश्यकता को बताया और विज्ञान,दर्शन और धर्म के समन्वय की बात की। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ऋचा द्विवेदी और संचालन डॉ. राकेश कुमार मिश्र ने किया। द्वितीय अकादमिक सत्र 'भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और साहित्य' के वक्ता संजय जायसवाल ने अपने वक्तव्य में कहा,'भारतीय ज्ञान परंपरा कोई एकरेखीय धारा नहीं है, बल्कि अनेक जातियों, भाषाओं और समुदायों की साझा यात्रा है। इसे समझने के लिए तीन दृष्टिकोण जरूरी हैं, डी-कोलोनाइजेशन, डी-मिस्टिफिकेशन और इंक्लूसिवनेस। 'सदीनामा' मासिक पत्रिका के संपादक जितेंद्र जितांशु ने भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास,चीन के कन्फ़्यूशियस, यूनान और भारत,मार्क्स, डेमोक्रेसी, ईसा मसीह समेत कई उदाहरणों द्वारा भाषा,संस्कृति, और विचारधारा की स्थायित्व शक्ति,विलय और पुनरुद्धार की संभावना बताई। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने साहित्य में ज्ञान परंपरा के विकास को रेखांकित किया। उन्होंने भारतेंदु,महावीर प्रसाद द्विवेदी, आर्यभट, कौटिल्य आदि के शास्त्रों के ऐतिहासिक योगदान, शोध की भारतीय प्रविधि, नाट्यशास्त्र ,पाणिनी, वासुदेव शरण अग्रवाल, औपनिवेशिकता, डिनाइजेशन, लोक-प्रतिबद्धता, समावेशिकता, और संवाद के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक महत्व को रेखांकित किया। आलोक टंडन ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को केवल शास्त्रों और परंपरागत धारणाओं तक सीमित कर देखने के बजाय उसे वैज्ञानिकता,तर्क और विवेक की कसौटी पर परखना होगा। संचालन डॉ. एकता हेला और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अमरेंद्र कुमार शर्मा के ने किया। तृतीय अकादमिक सत्र 'भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता' के वक्ता अमरेंद्र कुमार शर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री स्वर पर अपनी बात रखी। अगले वक्ता राकेश कुमार मिश्र ने आधुनिकता को परिभाषित करते हुए पूर्व और पश्चिम की अवधारणा को बतलाया जो अन्य को देखने की अलग दृष्टि विकसित करती है। प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर ने कहा कि भारतीय ज्ञान-परंपरा को केवल अतीत का गौरव मानकर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के विज्ञान-दर्शन और वैश्विक चुनौतियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। प्रोफेसर निर्मल नारायण चक्रवर्ती ने भारतीय ज्ञान परंपरा को मधुसूदन सरस्वती के 'प्रस्थान भेद' से जोड़कर व्याख्यायित किया। संचालन डॉ. आशुतोष व्यास और धन्यवाद ज्ञापन डॉ.अमित राय द्वारा किया गया। चतुर्थ अकादमिक सत्र 'भारतीय ज्ञान परंपरा और लोक का विज्ञान' सत्र के वक्ता डॉ. शिशिर सिंह ने भारतीय ज्ञान की लोक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली को उदाहरणों से बतलाया तथा यह प्रणाली आज भी कैसे कारगर है बताया। दीपक कुमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को आदिवासी लोक में प्रचलित प्रणालियों को लोक कथाओं के माध्यम से बताते हुए इनकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता को भी बतलाया। प्रोफेसर मधु कपूर ने भारतीय दर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कलेक्टर ने अभिप्रेरित किया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बालिकाओं को

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा जिला मुख्यालय पर संचालित सशक्त वाहिनी की क्लास में पहुंचकर बालिकाओं को मार्गदर्शन देते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभिप्रेरित किया है। उन्होंने कहां की आप लोग अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें मोबाइल का उपयोग सिर्फ अपने परिजनों एवं आवश्यक कार्य होने पर ही उपयोग करें आप लोग प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश रोजगार निर्माण, रोजगार समचार न्यूज पेपर के सांथ प्रतियोगिता दर्पण भी पड़े।

एसएससी की एमटीएस सीएचएसएल आइटीबीपी सीआईएफ बीएसएफ आर ए एफ सीआईएसफ सीआरपीएफ एनसी बी की तैयारी करें वैकेंसी अधिक रहती है और इंडियन भारत गार्डन में भी बहुत स्कोप रहता है उसकी भी तैयारी करें एमपीपीएससी

यूपीएससी के अलावा भी कई परीक्षाएं होती हैं उनकी परीक्षाएं दें।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने बालिकाओं से कहा कि आप लोग अपने स्वयं के नोट्स बनाकर तैयारी करें और इंग्लिश बोलना सीखे जिसके लिए हिंदी और इंग्लिश अखबार पढ़ें मैंगनीज और पेपर सॉल्व की बुक पडे।साथ ही बालिकाओं को बताया कि आप लोग अपनी हेल्थ में सुधार लाएं जिसके लिए अच्छा पौष्टिक आहार लें क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्त होने से ही हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं

आज सशक्त वाहिनी की क्लास में गंजबासौदा की बेटी आकांक्षा जैन जिन्होंने वर्ष 2023 की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएफएस में सिलेक्शन हुआ के द्वारा बालिकाओं को मोंटिवेट किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आप लोग एक लक्ष्य बनाकर अपनी तैयारी करें और अपने स्वयं के नोट्स बनाएं जिससे आपको हर एक चीज हमेशा याद रहेगी और उनके द्वारा बताया की कोई भी परीक्षा निकालना मुश्किल नहीं है उसके लिए हमें अपनी मेहनत के साथ अन्य चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ उसी का फोकस करना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है आपको जरुर सफलता मिलेगी।

श्रीमती विनीता लोढ़ा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया की ऐंसी बालिकाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रायवेट कोचिंग नहीं लें पा रही है उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा कराई गई है जिसमें विषय विशेषज्ञ द्वारा अलग अलग विषय की तैयारी के सांथ ही फिजिकल क्लास भी कराई जा रही है सशक्त वाहनी अभियान अंतर्गत संचालित निःशुल्क कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं को शासकीय नौकरी मे चयन हेतु अवसर प्रदान करना है।

सशक्त वाहिनी कक्षा के सहायक नोडल अधिकारी श्री संतोष रघुवंशी महिला एवं बाल विकास अनुज जैन एवं प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र श्रीवास एवं सौरव रघुवंशी उपस्थित रहें।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विदिशा जिले के चिन्हित ग्रामों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से शेष रहे हितग्राहियों के आधार कार्ड, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, बनाए जाने के साथ-साथ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, राशन कार्ड-पात्रता पर्ची और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 अगस्त को ग्राम बहलोट और महमूदा में शिविर का आयोजन कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही साथ 12 अगस्त को पिपरिया जाजोन, मसूदपुर, 13 अगस्त को सकरौली, मंगरोद, 14 अगस्त को चोरावर, कुराबद, 19 अगस्त को वेदक चौड़ा, सैरवासा, 20 अगस्त को कुल्हार, काजी करोदा, 21 अगस्त को औरंगपुर, बरोदिया, 22 अगस्त को उदयपुर, मुर्तजा नगर, 25 अगस्त को गोरिया, लखूली, 26 अगस्त को नौघई, पांचमा, 27 अगस्त को बरमढ़ी, त्यौंदा, 28 अगस्त को दैलवाड़ा, पधार और 29 अगस्त को बंजरिया और करीमपुर में भी शिविरों का आयोजन हुआ है।

सहकारी समितियों में उर्वरकों का तीव्र गति से भंडारण शुरू

विदिशा (निप्र)। आगामी रबी फसल हेतु सहकारी समितियों में उर्वरकों का तीव्र गति से भंडारण शुरू हो गया है। रबी फसल की बुवाई में अभी 2 माह का समय है, किन्तु जिले की सहकारी समितियों में अभी से उर्वरकों का तीव्र गति से भंडारण शुरू हो गया है। जिले के सौराई रेक प्वाइंट पर विगत 15 दिनों में 2 दिन के अंतराल से निरंतर खाद की रेक आ रही हैं। रेक से ट्रकों में खाद लोड होकर सहकारी समितियों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि कृषकों को खाद के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े और नजदीकी समिति से आसानी से खाद मिल जाए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले की सभी 154 सहकारी समितियों में यूरिया खाद की उपलब्धता हो गयी है। इसी क्रम में आज सोमवार को सौराई रेक प्वाइंट पर एचयूएलआर कम्पनी की यूरिया खाद की रेक लगी है, जिससे 403 मी. टन यूरिया खाद सहकारी समितियों में भेजा जा रहा है। वर्तमान में सहकारी समितियों में 7100 मी. टन यूरिया व 3200 मी.टन डीएपी एवं 3300 मी. टन काम्पलेक्स उर्वरकों का स्टॉक है। इस वर्ष कृषकों को बुवाई हेतु उर्वरकों के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला प्रशासन द्वारा इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। जिले में उर्वरको की रेक निरंतर आ रही हैं और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। आगामी 2 दिवस में एनएफएल डीएपी मात्रा 2895 मी.टन का रेक भी जिले को प्राप्त हो रहा है। शासन का प्रयास है कि बुवाई के 1 माह पूर्व ही कृषकों को उनकी आवश्यकता का खाद उपलब्ध करा दिया जाए।

संबल योजना के लंबित अपील प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाएं : कलेक्टर

बैतूल (निप्र)। संबल योजना के लंबित अपील प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित कराएं। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समयसीमा की बैठक में सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने रीडर्स को प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के लिए ताकीद करें। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले और जनपद स्तर पर ई ऑफिस प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला और जनपद स्तरीय अधिकारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी रोस्टर अनुरूप अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। रोस्टर के अनुसार निरीक्षण नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समग्र ई केवाईसी अभियान की प्रगति की भी कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद और निकायवार समीक्षा की। उन्होंने जनपद सीईओ घोड़ाडोंगरी, सीएमओ शाहपुर को विशेष ध्यान देकर प्रगति लाने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की गिरदावरी की जानकारी भी ली। उन्होंने उप संचालक उद्यानिकी को पूरी गंभीरता से व्यवस्थित गिरदावरी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को लंबित शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 50 दिवस से अधिक की शिकायतों का भी समाधान किए जाने के निर्देश दिए। समय सीमा अवधि के पत्रों की भी कलेक्टर ने जानकारी ली और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि माननीय न्यायालयीन प्रकरणों में पूरी गंभीरता से जवाब प्रस्तुत किया जाएं। उन्होंने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम इसकी सतत मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।

श्री कृष्ण गौशाला में लंपी रोग से बचाव हेतु टीकाकरण

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले की सभी गौशालाओं के पशुओं की बेहतर देखभाल हो साथ ही समय चक्र अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम अभियान के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशों के अनुपालन में जारी कार्यवाही की जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उपसंचालक डॉ के एन शुक्ला ने बताया कि गंजबासौदा विकास खंड के ग्राम कालापाठा में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आज पशुपालन विभाग द्वारा लंपी स्किन डिज़ीज़ से बचाव हेतु व्यापक टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन किया गया। इस अभियान के तहत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी घटेरा श्री ए.के. शर्मा द्वारा गौशाला में संरक्षित सभी गौवंश का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि - ÷लंपी रोग पशुओं में तेजी से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। समय पर टीकाकरण ही इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय है। इस अभियान से गौवंश सुरक्षित रहेंगे और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।÷ गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कहा - ÷पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर दी जा रही सेवाएँ हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं। हम विभाग के आभारी हैं कि उन्होंने गौवंश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।÷ साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में ऐसे ही सहयोगात्मक अभियान जारी रहें, जिससे जिले की सभी गौशालाएँ लंपी जैसी संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।

टीएल बैठक में ने की सीएम हेल्पलाईन और योजनाओं की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। सीएम हेल्पलाइन जनसमस्याओं के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त प्रकरणों के निराकरण में और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। सभी अधिकारी गंभीरता से रुचि लेते हुए प्रकरणों का प्रभावी निराकरण कराएं। इसके लिए अधिकारी हितग्राहियों से स्वयं चर्चा करें तथा शत-प्रतिशत सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभागीय गतिविधियों, अभियानों तथा योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायत, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, सहकारिता सहित अन्य विभागों की

सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों तथा निराकरण की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर बेहतर कार्य किया जा रहा है, वह और अधिक बेहतर काम करने के लिए प्रयास करें। सीएम हेल्पलाईन निराकरण में धीमी गति से काम कर रहे अधिकारियों को निराकरण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी एक सप्ताह में अधिक से अधिक शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। कोई भी शिकायत निम्न गुणवत्ता से बंद ना हो और ना ही कोई शिकायत नॉन अटेंडेन्ट रहे। प्रत्येक शिकायत पर समयावधि में नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन और सीएमएचओ को शिकायतों के निराकरण में गंभीरता नहीं दिखाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में 50 दिवस से अधिक समयावधि की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि इन शिकायतों के निराकरण में गति नहीं आई है। एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरिंग करें तथा निराकरण में तेजी लाएं। उन्होंने ऊर्जा विभाग, शहरी विकास, राजस्व, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतें नॉन अटेन्डेन्ट रहने पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा नियमित रूप से सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का समयावधि में निराकरण हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को दिशा-निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही समग्र ई-केवायसी कार्य में तेजी लाने हेतु सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। इसी प्रकार वनाधिकार धारकों को केसीसी प्रदाय करने संबंधी कार्य की जानकारी लेते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को केसीसी से लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। एक बगिया माँ के नाम अभियान की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को पौधरोपण हेतु चिन्हित कर लाभान्वित करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ और अधिकारियों को दिए गए।

इसी प्रकार नगरीय निकायों में गीता भवनों के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने तथा मण्डीदीप और रायसेन में नवीन फायर स्टेशन निर्माण हेतु भी भूमि चिन्हांकित करने हेतु पीओ डूडा तथा एसडीएम को निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, टेक होम राशन, पोषण आहार वितरण तथा नवीन आंगनवाड़ी भवनों की प्रगति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सभी पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाने के निर्देश दिए गए। वन विभाग की समीक्षा करते हुए अवैध कटाई, उत्खनन और परिवहन में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

राइट क्लिक

मराठा आरक्षण-जरांगे जीते या फडणवीस के जाल में उलझे?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने की अपनी पुरानी मांग को लेकर मुंबई में पांच दिनों से अनशन कर रहे, मराठा नेता मनोज जरांगे का आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया। कहा गया कि जरांगे सरकार से अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। उन्होंने भाजपा की फडणवीस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है? और जो हुआ है, वो किसकी राजनीतिक जीत है? जरांगे की या राज्य के 'चाणक्य' मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की? दोनों के बीच जो सहमति बनी है, उसकी गहराई से पड़ताल करें तो जरांगे के हाथ सिर्फ मराठों को कुणबी मानकर ओबीसी प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में तत्कालीन हैदराबाद रियासत का गजेटियर लागू करने की मांग माने जाने की कामयाबी लगी है। वह भी केवल मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए, जहां से जरांगे आते हैं। यह प्रमाण पत्र भी ग्राम स्तर जाति की सूक्ष्म जांच के बाद दिए जाएंगे। बाकी महाराष्ट्र में यह व्यवस्था लागू करने के बारे में सरकार ने सिर्फ विचार का आश्वासन दिया है। मराठी कहावत 'दूध की प्यास, छाछ से बुझाने' के अनुसार भले जरांगे इसे अपनी जीत मानें, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने उन्हें झुनझुना थमाने के अलावा कुछ नहीं दिया है। कारण साफ है कि किसी भी जाति की श्रेणी बदलना आसान नहीं है और ऐसा करना जानबूझकर अंगारों से खेलना है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने दोहरी चाल कर जहां इस अंगारे को हौले से छेड़ भी दिया है और खुद 'नियमानुसार आरक्षण' देने की आड़ में मराठा हितैषी साबित करने की कोशिश कर, जरांगे के अब तक के सबसे बड़े आंदोलन की हवा भी निकाल दी है। उधर मराठों को ओबीसी केटेगरी में आरक्षण देने के खिलाफ राज्य के ओबीसी समुदायों ने खम ठोंकना शुरू कर दिया है, जिससे प्रदेश में मराठा-ओबीसी संघर्ष के एक नए दौर में प्रवेश की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा इस समूचे प्रकरण में कोर्ट का भी परोक्ष रूप से इस्तेमाल कर लिया गया है।

वैसे राज्य सरकार ने जरांगे की जो मांगें मानी हैं, उनमें हैदराबाद गजेट लागू करने के अलावा सतारा और औंध रियासत के गजेट्स लागू करने की प्रक्रिया में कानूनी अड़चनें दूर 15 दिनों में दूर करने, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को 15 करोड़ की आर्थिक सहायता और पात्रता अनुसार सरकारी नौकरी, 58 लाख कुणबी रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत स्तर पर करने तथा मराठा आरक्षण के संदर्भ में पूर्व में गठित वंशावली (शिंदे) समिति का कार्यकाल बढ़ाना शामिल है। यानी सरकार ने जरांगे की कुल 8 में 6 मांगे मानी हैं और वो भी आंशिक रूप से। इसमें भी कई व्यावहारिक पेंच हैं।

पहली नजर में देखें तो जरांगे का आंदोलन मुंबई हाई कोर्ट की सख्ती के बाद समाप्त हुआ ज्यादा प्रतीत होता है। क्योंकि आंदोलनकारियों ने उन सभी शर्तों का उल्लंघन कर आंदोलन जारी रखा था, जिनके आधार पर कोर्ट द्वारा उन्हें मुंबई जैसे अत्यंत व्यस्त शहर के आजाद मैदान में एक दिन के सशर्त आंदोलन की अनुमति दी गई थी। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों में जोश तो था, लेकिन लंबा आंदोलन चलाने के लिए जरूरी रणनीति और तैयारियों की उन्हें न तो समझ दिखी और न ही उसका इंतजाम था। देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने भी सीधे पंगा मोल न लेकर जरांगे समर्थकों को आंदोलन करने की इजाजत तो दी, लेकिन उसके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आंदोलन स्थल पर न तो पानी, खाने अथवा टॉयलेट आदि का इंतजाम था। जैसी कि आशंका थी कि आंदोलन की अनुमति सिर्फ 5 हजार लोगों की थी, आ गए लाखों मराठे। इससे स्वत: अव्यवस्था फैली। सरकार ने कहा कि आंदोलनकारी कोर्ट के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं। वहां पुलिस का इंतजाम था, लेकिन कार्रवाई के आदेश नहीं थे। सरकार शायद हालात ज्यादा बिगड़ने और फिर सख्ती से दखल देने का इंतजार कर रही थी। उधर हाई कोर्ट भी आंदोलनकारियों की अनुशासनहीनता से नाराज था। आंदोलन के कारण दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए और हाई कोर्ट जजों को भी पैदल अपने कोर्ट तक जाना पड़ा। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की जो दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उनमें दूसरी जज आरती साठे, हाल ही में हाई कोर्ट जज बनी हैं और पूर्व में भाजपा की प्रवक्ता भी रह चुकी है। आंदोलन अनियंत्रित होता देख कोर्ट ने आदेश दिए कि आंदोलन मंगलवार तक हर हाल में खत्म करें अन्यथा कोर्ट को कोई सख्त आदेश देना पड़ेगा। आखिर कोर्ट के दबाव के आगे जरांगे को झुकना ही पड़ा। साथ ही इस बात कर खतरा भी था कि हालात बिगड़े तो आंदोलन जरांगे के काबू से बाहर हो जाएगा।

जरांगे का मराठा आरक्षण आंदोलन भी मूलत: राजनीतिक ही है। क्योंकि उनकी जो मांग है, उसे कोई भी राजनीतिक दल पूरा नहीं कर सकता। वो मराठा को सामान्य वर्ग से ओबीसी में स्थानांतरित कर आरक्षण मांग रहे हैं। उनके आंदोलन को राज्य के शरद पवार जैसे बड़े मराठा नेताओं का परोक्ष समर्थन है। जरांगे की मांगे संविधानिक दृष्टि से कोई भी सरकार मान्य नहीं कर सकती, यह जानते हुए भी कुछ मराठा नेता इसे समर्थन इसलिए देते हैं कि इससे सत्तारूढ़ सरकार परेशानी में आती है। देवेन्द्र फडणवीस इस दांव को बखूबी समझते हैं। इसलिए उन्होंने जरांगे से चर्चा के लिए भाजपा के मराठा नेता व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में कैबिनेट सब कमेटी बनाई और उन्हें ही बातचीत के अधिकार दिए। फडणवीस बाहर यही कहते रहे कि मैं मराठाओं को कुणबी ओबीसी श्रेणी में 'कानून के मुताबिक' आरक्षण देने का समर्थक हूं। मैंने बतौर सीएम अपने पिछले कार्यकाल में इसकी पहल भी की थी, लेकिन बाद की उद्धव ठाकरे सरकार ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि ओबीसी के आरक्षण को तिल भर कम करके किसी दूसरे को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस तरह फडणवीस एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। वो जरांगे को भी खुश कर रहे थे तो राज्य में ओबीसी के मसीहा भी बने हुए थे।

अब सरकार द्वारा राधाकृष्ण विखे पाटिल उप समिति की जरांगे से हुई चर्चा के बाद स्वीकार मांगों को समझें। सरकार ने जरांगे की सिर्फ इतनी मांग मानी है कि पूर्व में हैदराबाद रियासत में जारी गजेटियर के अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी मानकर उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन वह भी सूक्ष्म जांच के बाद। क्योंकि कौन-सा मराठा सामान्य वर्ग में और कौन सा कुणबी, यह तय करना आसान नहीं है। इसमे कई पेंच हैं। इसका आधार क्या होगा? इसे कैसे साबित किया जा सकेगा? तथा इस पर अगर गंभीर आपत्तियां लगीं तो उनका निराकरण कैसे होगा? मजेदार बात यह है कि वीर शिवाजी पर अभिमान करने वाले मराठे, सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए अब 'कुणबी' कहलाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें वो जाति व्यवस्था में अपने से कमतर मानते रहे हैं। यूं कुणबी भी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन 96 कुली मराठा अपने को उनसे ऊंचा और शासक क्षत्रिय मानते हैं। नई व्यवस्था से जो नया घालमेल होगा, जिससे राज्य में नए जातीय संघर्ष बढ़ सकता है। दूसरे, मराठे पूरे महाराष्ट्र में फैले हैं, लेकिन जरांगे की मांग केवल आठ जिलों के लिए मानी गई है। दूसरी तरफ फडणवीस के करीबी वरिष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते ने जरांगे से समझौता होने के तत्काल बाद ऐलान कर दिया कि सामान्य वर्ग में आने वाले मराठाओं को हैदराबाद गजेटियर के अनुसार ओबीसी में स्थानांतरित करने की कोशिश पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इसके सबूत मांगेगा और मामला फिर टायं-टायं फिस्स हो जाएगा। और सरकार इसकी आड़ में कटघरे में खड़ी होने से बच जाएगी। हालांकि मराठा नेता शरद पवार कह चुके हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में लागू पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया जाए तो राज्य में मराठों को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन यह बहुत मुश्किल है और केन्द्र सरकार संसद में संविधान संशोधन करे तो ही संभव है। और एक बार 'जाति श्रेणी परिवर्तन' का पिटारा खुल गया तो सभी जातियां अपनी सुविधा और स्वार्थ से जाति श्रेणी बदलाव की मांग करने लगेंगी। ऐसे में अराजकता की स्थिति बन सकती है। कोई भी सरकार यह खतरा शायद ही मोल ले।

उधर राज्य ओबीसी समुदाय भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी वर्ग की बैठक बुलाकर मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। ओबीसी जरांगे की चालों को भी देख रहा है और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की चाल को भी बूझ रहा है। दरअसल जरांगे की मांग मानने का असर केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सीमित न रहकर दूरगामी होने वाला है। क्योंकि देश में अगले साल होने वाली जाति जनगणना के बाद ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण भी होगा। ऐसे में मराठा नेता चुनाव टिकट के लिए ओबीसी सीटों पर दावा ठोंकेंगे, जो ओबीसी कभी नहीं होने देंगे। उनका वाजिब सवाल है कि जब गरीब मराठाओंको सरकार ने अनारक्षित वर्ग में 10 फीसदी आरक्षण दे दिया है तो उन्हें फिर कुणबी (जो मूलत: कृषक समुदाय है) में आरक्षण क्यों चाहिए? गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 28 से 33 फीसदी तक है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या 33 प्रतिशत है। यानी दोनो की आबादी लगभग बराबर है। ऐसे में राजनीतिक संतुलन साधना तार पर चलने की कवायद है, जिसे फडणवीस बड़ी चतुराई से अंजाम दे रहे हैं। जबकि खुद फडणवीस ब्राह्मण हैं।

खास बात यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री तथा मराठा नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खुद को इस चर्चा से दूर रखा। कुल मिलाकर संदेश यही है कि जरांगे फडणवीस के जाल में उलझ कर रह गए हैं। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। खतरा राज्य में जातीय टकराव के गंभीर मोड़ लेने का ज्यादा है।

इंदौर में एक और नवजात की मौत...चूहे ने कुतरा था

एमवाय अस्पताल की लापरवाही से गई जान; हाईलेवल कमेटी करेगी जांच

इंदौर (नप्र)। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती एक और नवजात की बुधवार को मौत हो गई। चूहों ने सोमवार को उसके हाथ-पैर कुतरे थे। इससे पहले मंगलवार को भी एक नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया था।

इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर एक महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में दो नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया और अन्य को शोकॉज नोटिस दिया है। मामले की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई गई है।

हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने से मौत होने की बात से इनकार किया है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की मौत इंफेक्शन से हुई है। नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ पर कार्रवाई से नर्सिंग ऑफिसर्स में आक्रोश है। उनका कहना है कि इसमें सीधे तौर पर उनका कोई दोष नहीं है। जिम्मेदार वरिष्ठों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन हमें निशाना बनाया गया।

परिजन ने नहीं कराया पोस्टमॉर्टम, एक बच्चे की रिपोर्ट आना बाकी- जिस बच्चे की मौत बुधवार को हुई, वह देवास की रहने वाली रेहाना का है। परिवार ने बच्चे का पोस्टमॉर्टम कराने से

इनकार कर दिया है। वे शव को लेकर रवाना हो गए। वहीं मंगलवार को जिस बच्चे की मौत हुई थी वह खंडवा के पास एक गांव की रहने वाली लक्ष्मीबाई का है। उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आना बाकी है।

आयोग ने संज्ञान लिया; उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच- नवजात की मौत के मामले में बुधवार को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अस्पताल के अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं। एक महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। वहीं, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी में डॉ. एसबी बंसल, डॉ. शशि शंकर शर्मा, डॉ. अरविंद शुक्ला, डॉ. निर्भय मेहता, डॉ. बसंत निगवाल और नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर दयावती दयाल शामिल हैं। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी सीएम बोले- यह गंभीर मामला है, तुरंत कार्रवाई हुई- उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह गंभीर मामला है, जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई हुई है। आमतौर पर पेस्ट कंट्रोल सही समय पर कर दिया जाता तो चूहों नहीं रहते, लेकिन जिस प्रकार से चूहा दिख रहा है इसे साफ है कि पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया।

पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है और टर्मिनेट करने का नोटिस दिया गया है।

नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटाया गया है। दो नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। शिशु रोग विभाग के एचओडी को नोटिस दिया गया है।

पटवारी बोले- भ्रष्टाचार से बीजेपी नेताओं का पेट भर रहा

एमवाय की घटना पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने लिखा- बीजेपी के 22 साल का यह असली चेहरा है। एमवाय में चूहों की हरकत यह पहली बार नहीं हुई। नवजातों को चूहों ने नहीं, भ्रष्टाचारी प्रशासन ने क्षति पहुंचाई है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार में रीढ़ की हड्डी है तो क्या अधीक्षक को सजा दे सकते है? नहीं दे सकते। वह सिर्फ छोटे से वार्ड बॉय को हटाएंगे। यह व्यवस्था क्या है? एमवाय में अराजकता क्यों है? चूहे बच्चों को खा रहे हैं, भ्रष्टाचार से बीजेपी के नेताओं का पेट भर रहा है। यह दोनों बातें बच्चों की जान लेने का कारण है। जितना दोषी वह चूहा है, उससे ज्यादा दोषी यह तंत्र और व्यवस्था है।

ईद मीलादुन्नबी मनाने की तैयारियाँ, मुख्य जुलूस कल निकलेगा

भोपाल। ऑल इण्डिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के चेयरमैन हज़रत पीरज़ादा हाफ़िज़ अहमद शाहमीर खुर्रम मियाँ चिश्ती साहब एवं ईद मीलादुन्नबी समारोह के संयोजक श्री अब्दुल नफीस ने बताया कि पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद स.अ.व. साहिब के पवित्र जन्मदिवस ईद मीलादुन्नबी का शानदार जश्न मनाने की तैयारियों को लेकर शहर के सभी मुसलमानों में जोश-ओ-ख़रोश का माहौल है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस बार भी मुसलमानों द्वारा 5 सितम्बर 2025 को ईद मीलादुन्नबी का परंपरागत त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर में चौराहों सहित अनेकों स्थानों पर हरे झण्डे फेहराए जाएंगे और मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों, इमाम बाड़ों ,घरों,दुकानों पर चिरागाँ कर रौशनी की जाएगी तथा नियाज़, फातेहा,दरूद ख्वानी, क़ुरआन ख़्वानी के बाद तबररूक तक़सीम किया जाएगा।

ईद मीलादुन्नबी का परम्परागत जूलूस 5 सितम्बर को दोपहर में मंगलवारा चौराहे से रवाना होगा जिसमें देश की अनेक हस्तियों का सम्मान भी किया जाएगा क्योंकि इसलिए इस बार गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की गंगा जमनी तहज़ीब के तहत कमेटी एआईएमटीसी की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के कार्यक्रम संयोजक अब्दुल नफीस ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के राष्ट्रीय सदस्य एवं भोपाल मध्य क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद की खुसुसी मौजूदगी में जुलूस का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीरज़ादा हाफ़िज़ अहमद शाहमीरी खुर्रम मियाँ चिश्ती साहब करेंगे तथा अनेक हस्तियॉ भी जूलूस में शामिल होंगी। इस दिन सुबह से ही मोहल्लों, कॉलोनियों में ईद मीलादुन्नबी का जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा शहर की अनेक मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, दरगाहों, ज़ियारतगाहों, इमामबाड़ों, आस्तानों आदि में ज़िक्रे इलाही, क़ुरआन ख्वानी, दरूद ख्वानी के परम्परागत कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि मोहल्लों में परचम कुशाई करने के बाद मुस्लिम समाज के बुर्जुगों के साथ अखाड़ों के उस्ताद, ख़लीफाओं द्वारा सलामी पेश की जाएगी। सभी उस्तादों एवं ख़लीफाओं का भी जुलूस में मंच पर रंग बिरंगी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जाएगा।

मंदसौर में जिला आबकारी अधिकारी के घर ईडी का छापा

मंदसौर (नप्र)। मंदसौर के पूर्व जिला अधिकारी बद्री लाल डांगी के यश नगर स्थित आवास पर बुधवार सुबह ईडी ने छापा मारा है। हाल ही में बद्री लाल डांगी डांगी का तबादला दतिया हुआ था और सोमवार को उन्होंने दतिया जिला आबकारी अधिकारी के रूप में ज्वॉइनिंग ली है। जानकारी के मुताबिक, ईडी के छापे के समय पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के घर में कोई मौजूद नहीं था। इंदौर और भोपाल की 2 टीमों ने यहां दबिश दी। बीएल डांगी मंदसौर में नौकरी के दौरान काफी विवादों में रहे, उनके ऊपर पिपलिया मंडी शराब दुकान से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था।

कछुआ के नाम पर ब्लैकमेल, 40 घंटे डिजिटल अरेस्ट

उज्जैन की महिला से धमकाकर गहने गिरवी रखवाए; अकाउंट में डलवाए 5 लाख रुपए

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के बसंत विहार में रहने वाली एक महिला साइबर फ्रॉड में ऐसी फंसी की 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही। महिला ने अपने गहने गिरवी रखकर 5 लाख रुपए ठगों को दे दिए। पुलिस ने एक युवती युक्ति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2.89 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। एक आरोपी युवक और युवती प्रेमी-प्रेमिका बताए जा रहे हैं।

एसआई जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट की गई महिला सरोज उज्जैन में अकेली रहती थी। उसके पति रिटायर्ड फौजी थे और उनकी मौत हो चुकी है। बच्चे भी बाहर काम करते हैं।

एक ठग बोला- मैंने कछुए पाले थे तो गिरफ्तारी हुई थी- एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन में रहने वाली सरोज माली (50) तबीयत खराब होने के चलते नागदा अपनी बहन के घर आई थी। 12 अगस्त को सरोज के पास एक अनजान महिला का कॉल आया। महिला ने खुद को बिरला ग्राम थाने की पुलिसकर्मी बताते हुए घर में कछुए और मछली पालने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। कॉलर ने सरोज को कहीं भी कॉल करने से मना कर दिया।

12 से 14 अगस्त तक महिला डिजिटल अरेस्ट रही। एक अन्य युवक ने सरोज को कॉल कर बताया कि उसने भी मछली और कछुए घर में रखे थे, जिसके चलते उसे भी गिरफ्तार किया गया था। सरोज डर गई और उसने अपने गहनों को गिरवी रखकर 5 लाख 9 हजार रुपए बदमाशों को दे दिए। 14 अगस्त को बदमाश घर आकर उससे रुपए ले गए। आरोपी ने खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर भी महिला को धमकाया। रुपए देने के बाद ठगी का एहसास होते ही सरोज ने 15 अगस्त को थाना बिरला ग्राम में रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिसने रेप किया, पीड़िता को उसके घर फिर भेजा, दोबारा रेप

पन्ना सीडब्ल्यूसी का कारनामा

- अध्यक्ष, 5 सदस्य, महिला बाल विकास अधिकारी समेत 10 पर एफआईआर

छतरपुर/पन्ना (नप्र)। पन्ना में बाल कल्याण समिति ने नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया, जहां उससे दोबारा रेप किया गया। छतरपुर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, पांच सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक, काउंसलर, केस वर्कर और एक अन्य महिला समेत कुल 10 लोगों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों के घर पर दबिश दी है। समिति के सदस्य आशीष बॉस को गिरफ्तार किया गया है। अन्य सदस्यों के घर भी पुलिस पहुंची है। परिजन से भी पूछताछ की गई है। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी अवधेश कुमार सिंह को भी नोटिस दिया गया है।

लवकुशनगर (छतरपुर) एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि समिति और अधिकारियों के गलत फैसले से पीड़िता को दोबारा दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा। जांच में यह भी सामने आया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की। गलत निर्णय करने वालों और मामले को छिपाने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

छतरपुर एएसपी विदिता डांगर का कहना है कि दुष्कर्म की एक घटना में बाल कल्याण समिति ने पीड़िता को आरोपी की भाभी, जो कि पीड़िता की चचेरी बहन थी, उसके सुपुर्द किया था। इस कारण आरोपी को जमानत में लाभ मिला। बाहर आने के बाद आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन पर दर्ज हुई एफआईआर

आरोपियों में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष भानू जड़िया और सदस्य अंजलि भदौरिया, आशीष बॉस, सुदीप श्रीवास्तव व प्रमोद कुमार सिंह पर पॉक्सो एक्ट की धारा 17 (अपराध को बढ़ावा देने पर) लगाई गई है।